mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-02 अंक-195 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

मनेन्द्रगढ़
16 जुलाई 2026 गुरुवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

जगन्नाथ पुरी रथयात्रा आज से

● 6 महीने पहले से होटल बुकिंग ● 1500 का कमरा 50 हजार में मिल रहा

» हावड़ा में जगन्नाथ यात्रा गोद में निकलती है

पुरी,एजेंसी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा 16 जुलाई, गुरुवार से शुरू होगी। यह भव्य उत्सव 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। रथयात्रा को लेकर पुरी के होटल और लॉज पूरी तरह फुल हो चुके हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक, इस साल फरवरी से ही बुकिंग शुरू हो गई थी। मंदिर और रथयात्रा मार्ग के आसपास के होटल-लॉज की सबसे ज्यादा मांग है। खासकर जिन होटलों की बालकनी या खिड़की रथयात्रा मार्ग की ओर खुलती है, उनके लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। पिछले साल के मुकाबले होटल और लॉज का किराया 10 गुना तक बढ़ गया है। जिन लॉज का सामान्य किराया 1500 से 2000 रुपए होता है, उनका किराया रथयात्रा के दौरान तीन दिन के लिए 50 हजार रुपए तक पहुंच गया है। पूरे शहर में करीब 1200 होटल हैं।

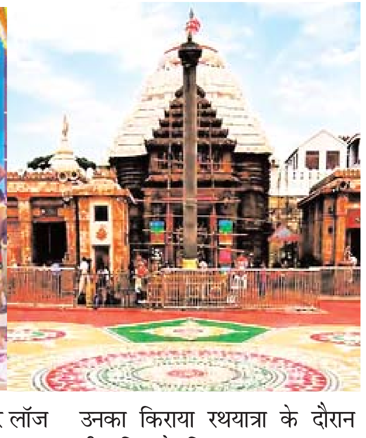

हावड़ा में प्रोफेसर की गोद बनती है भगवान जगन्नाथ का रथ

धर्म और आस्था की सीमाओं से परे पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हर साल एक अनोखी रथयात्रा निकाली जाती है। यहां न तो रस्सी से रथ खींचा जाता है और न ही विशाल रथ सजाया जाता है।

इसके बजाय कोलकाता के सेंट पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज के बांग्ला विभाग के प्रोफेसर डॉ. शेख मकबूल इस्लाम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह को अपनी गोद में लेकर करीब 400 मीटर की परिक्रमा करते हैं। इस यात्रा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदायों के लोग शामिल होते हैं। डॉ. इस्लाम 1992 से भगवान जगन्नाथ पर शोध कर रहे हैं और इस विषय पर 14 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। 1996 से उनके घर में भगवान जगन्नाथ का विग्रह स्थापित है, जबकि 2009 से वे हर साल रथपूजा के अवसर पर इस अनूठी परिक्रमा का आयोजन कर रहे हैं।

डॉ. शेख बोले- शरीर ही रथ है, तो अलग रथ क्यों? डॉ. शेख मकबूल इस्लाम इस परंपरा का आधार कठोपनिषद् के प्रसिद्ध श्लोक 'आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु...' को मानते हैं। उनके मुताबिक, इस श्लोक में शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और आत्मा को रथ का स्वामी बताया गया है। इसलिए जब शरीर ही रथ है, तो अलग रथ की जरूरत नहीं। वे पूरी तरह शाकाहारी हैं और भगवान जगन्नाथ के लिए अपने घर में पुरी की परंपरा के अनुसार 35 प्रकार का सात्विक भोग बनाकर विधि-विधान से अर्पित करते हैं।

: ब्रीफ बॉक्स :

नोएडा में 5-मंजिला मकान में भीषण आग, 2 की मौत

50 परिवारों को सीढ़ियां लगाकर रेस्क्यू किया, स्कूटी चार्जिंग के दौरान हुआ धमाका

नोएडा,एजेंसी। नोएडा में बुधवार दोपहर 5 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों के इमारत में फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हैं। सीढ़ियों और छतों के रास्ते लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि स्कूटी चार्जिंग के दौरान आग लगी। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग में 50 परिवार रहते हैं। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक को हिरासत में ले लिया है।

अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाए

सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक

तेल अवीव/ तेहरान/ वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, करीब सात घंटे तक चले ऑपरेशन में होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया।

उधर, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया।

भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका

रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी, संसद में बिल पेश, 5 देश निशाने पर

वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया गया है, जिसमें भारत, चीन समेत पांच देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इसमें हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान भी शामिल हैं।

बिल के मुताबिक, इन देशों से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकेगा। साथ ही रूस की ऊर्जा, वित्तीय और रक्षा व्यवस्था पर भी नए प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। इससे पहले बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया।

अगर यह बिल पास हो जाता है, तो अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसलिए टैरिफ लगाएगा, क्योंकि वह रूस से तेल खरीदकर उसकी कमाई बढ़ा रहा है। इस कदम का मकसद रूस के तेल कारोबार पर आर्थिक दबाव बनाना और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर करना है।

भारत ने पिछले महीने आधे से ज्यादा तेल रूस से खरीदा: भारत ने जून 2026 में रूस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो देश के कुल तेल आयात का 52.4% था। यानी पिछले महीने भारत में आयात होने वाले हर दो बैरल तेल में एक से ज्यादा बैरल रूस से आया। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। मई के मुकाबले जून में रूस से तेल आयात में करीब 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिल में रूस के ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्थानों, रक्षा औद्योगिक ढांचे, कारोबारियों और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

यूरोपीय देशों को टैरिफ में राहत देगा अमेरिका... सीनेट में पेश बिल के तहत 15 यूरोपीय देशों को प्रस्तावित 100% टैरिफ से छूट दी गई है। इन देशों को राहत इसलिए दी गई है, क्योंकि ये रूस से 15% से कम प्राकृतिक गैस खरीदते हैं और धीरे-धीरे उस पर अपनी निर्भरता भी कम कर रहे हैं। डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा कि यह बिल यूरोपीय सहयोगियों के खिलाफ नहीं है। इसका निशाना सिर्फ वे देश हैं।

सोनम वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई

कोर्ट ने केंद्र-दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

» वांगचुक 18 दिन से भूख हड़ताल पर, सेहत बिगड़ी

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 18 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधा और इलाज देने की मांग की गई है। इसे लेकर जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार से गुरुवार सुबह तक जवाब मांगा है। बार एसोसिएशन के बहिष्कार के कारण सरकार की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं होने के कारण सुनवाई कल होगी। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि भूख हड़ताल से वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही है। कोर्ट को अर्जेंट सुनवाई करनी चाहिए।

सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से स्टूडेंट्स निराश-सुप्रीम कोर्ट

» कहा- इसमें समस्याएं बोर्ड से पूछा सुधार के लिए अब तक क्या किया

नई दिल्ली,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि CBSE के डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम से स्टूडेंट्स में काफी निराशा है। CJI जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहयोग मांगा। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, 'देखिए, छोटे-छोटे बच्चों में कितनी निराशा है।' वहीं, जस्टिस बागची ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि सरकार से किसी टकराव की मंशा नहीं है, लेकिन व्यवस्था में कुछ समस्याएं हैं। कोर्ट ने CBSE की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि याचिका में जिन स्टूडेंट्स की व्यक्तिगत मार्कशीट से जुड़ी गड़बड़ियों का जिक्र था, उनमें से अधिकांश मामलों का समाधान कर दिया गया है। सरकार इस व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से ले रही है।

OSM सिस्टम और सरकार का पक्ष: CBSE का OSM यानी ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम ऐसी व्यवस्था है, जिसमें ऑन्सर शीट की स्कैन कॉपी कंप्यूटर पर जांची जाती है। शिक्षक कागज की कॉपी देखने के बजाय डिजिटल स्क्रीन पर मूल्यांकन करते हैं।

कांवड़ यात्रा के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि में कारसेवा का ऐलान

अखाड़ा परिषद बोला- अयोध्या की तरह मथुरा में जुटेंगे संत; राहुल-अखिलेश को न्योता देंगे

हरिद्वार,एजेंसी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब हरिद्वार के संत समाज ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि, मथुरा को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि कांवड़ मेला खत्म होने के बाद कार सेवा की तिथि घोषित की जाएगी।

मंगलवार को निरंजनी अखाड़े की बैठक हुई। इसके बाद रविंद्रपुरी महाराज ने कहा, 'सभी संतों ने आह्वान किया है कि 'चलो मथुरा चलें'। जैसे अयोध्या में साधु-संत और महात्मा बड़ी संख्या में पहुंचे थे, उसी तरह अब मथुरा में भी सभी संत-महात्मा और श्रद्धालु पहुंचेंगे।'

उन्होंने कहा कि कार सेवा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया जाएगा। कांवड़ मेला 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा।

रविंद्रपुरी महाराज ने कार सेवा को लेकर कहा, 'बिल्कुल, कार सेवा होगी। देशभर के साधु-संत, महात्मा और श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। जिनकी भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि में आस्था है, वे सभी वहां पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है कि मंदिर निर्माण का कार्य जल्द शुरू हो।'

उन्होंने कहा कि यह आह्वान केवल कुछ संतों का नहीं, बल्कि पूरे सनातन समाज का है। 'सभी की आवाज है- 'चलो मथुरा चलें'।

कर्नाटक: जज की कुर्सी पर काला जादू करने का आरोप

65 साल की महिला गिरफ्तार; केस का फैसला अपने पक्ष में कराना चाहती थी

चिक्कबल्लापुर,एजेंसी। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में 65 साल की महिला मंजुला को जज की कुर्सी पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि महिला लंबित पारिवारिक सिविल केस का फैसला अपने पक्ष में कराना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक, घटना 9 जुलाई की है। मामला 14 जुलाई को सामने आया।

जज की कुर्सी पर सरसों के दाने बिखेरे... पुलिस के मुताबिक, 9 जुलाई सुबह करीब 9:40 बजे फर्स्ट एडिशनल सीनियर सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में हुई। आरोप है कि महिला कोर्ट रूम में दाखिल हुई और जज की मेज पर 'पूजा' किए हुए सफेद सरसों के दाने बिखेर दिए।

सरकार ने फिर दोहराया- पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं

● यह विदेश यात्रा के लिए जारी होने वाला डॉक्यूमेंट

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के मुताबिक भारत सरकार देश से बाहर यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करता है।

मंत्रालय ने कहा कि यह एक डॉक्यूमेंट है जो पूरी जांच और वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है। इसका संचालन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 तथा पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत होता है। जायसवाल ने बताया कि देश के 8% से भी कम नागरिकों के पास पासपोर्ट है।

24 जून: सरकार ने पहली बार कहा- पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं: 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। यह बयान चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया में पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर दिया गया था। मंत्रालय ने 2013 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया था, जिसमें पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया था।

अधिकारियों ने यह भी बताया था कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत जनहित में जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार किसी गैर-भारतीय नागरिक को भी पासपोर्ट जारी कर सकती है। इसलिए पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सबूत है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार उन लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाने की जमीन तैयार कर रही है, जिनसे उसकी राजनीतिक असहमति है।

कांग्रेस ने पूछा- कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सबूत... विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद विपक्षी कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की थी। पार्टी ने सवाल उठाया कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो इसे किस आधार पर जारी किया जाता है।

राजस्थान-एमपी में मानसून थमा, यूपी-बिहार में भारी बारिश

● बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का असर ● ओडिशा में रेड अलर्ट

नई दिल्ली/ भोपाल/ जयपुर, एजेंसी। मानसून देशभर में एक जैसा काम नहीं कर रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में मानसून थम गया है। जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है।

मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ट्रफ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पूर्वी भारत में आकर रुक गई हैं। इससे पश्चिम-उत्तर भारत तक पर्याप्त मात्रा में नम हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए बारिश कम हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ दिनों बाद नया लो-प्रेशर सिस्टम बनने या मानसून ट्रफ के पश्चिम की ओर बढ़ने पर इन राज्यों में भी अच्छी बारिश शुरू हो सकती है। ओडिशा में बारिश का रेड अलर्ट है।

सैटेलाइट इमेज में देखें देश में मानसून की स्थिति... सैटेलाइट इमेज में बारिश का पूरा फोकस पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ऊपर घने बादल हैं। वहीं राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी महाराष्ट्र में बादल गायब हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बाढ़, लैंडस्लाइड और भारी बारिश से चार जिलों में नुकसान हुआ।

ओडिशा में जगन्नाथ रथयात्रा से पहले रेड अलर्ट... मौसम विभाग ने ओडिशा के कई इलाकों में रथ यात्रा के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें पुरी भी शामिल है। यह चेतावनी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र के कारण जारी की गई है।

बिहार-यूपी समेत कई राज्यों में आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश का अलर्ट

पटना, लखनऊ, एजेंसी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 22 राज्यों में तेज आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 12 घंटों के भीतर इन क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ झमाझम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव से आगामी 7 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मानसून काफी सक्रिय रहेगा और बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। ओडिशा के कई हिस्सों में आज अत्यंत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं, इसके विपरीत अगले 6-7 दिनों में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिम-मध्य भारत और उत्तर-पश्चिम के मैदानी इलाकों में बारिश का दौर थोड़ा धीमा रहेगा।

इन 22 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट: मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही आगामी दिनों में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश का अलर्ट है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश को लेकर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है।

उत्तर प्रदेश: यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश और तूफान की आशंका है। इनमें राजधानी लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, हरदोई, शाहजहांपुर, बाराबंकी, फतेहपुर, रायबरेली, कानपुर, इटावा, जालौन, बांदा, आगरा, औरैया और हमीरपुर शामिल हैं। प्रयागराज में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

बिहार: बिहार के किशनगंज और अररिया जिलों में आज तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, समस्तीपुर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सारण, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि, राजधानी पटना, गया और नालंदा में आसमान साफ रहेगा। पटना का आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, कटनी, शहडोल, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और मंदसौर में आज भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान 40-60 किमी प्रति घंटे की गति से धूल भरी आंधी भी चल सकती है। वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, सागर, जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना आदि जिलों में मौसम साफ रहेगा। भोपाल में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

हिमाचल प्रदेश: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पूरे हफ्ते जोरदार बारिश होने की संभावना है। आज राजधानी शिमला, कुफरी, सुंदरनगर, भुंतर, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ताबो, जोत, मुरारी देवी और नेरी में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 37 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है।

उत्तराखंड: उत्तराखंड के बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दूसरी ओर, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल में आसमान पूरी तरह से साफ रहने वाला है।

राजधानी देहरादून में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

कर्नाटक में जज पर जादू-टोना करने के प्रयास में महिला गिरफ्तार

चिक्काबल्लापुर,एजेंसीं। एक 65 वर्षीय महिला को कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में प्रथम अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज और जेएमएफसी कोर्ट के जज के कुर्सी पर जादू-टोना करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चिक्काबल्लापुर सिटी पुलिस के अनुसार, आरोपित महिला मंजुला ने अदालत परिसर में प्रवेश किया और जज की कुर्सी पर जादू-टोना करने के लिए जादुई सफेद सरसों के बीज छिड़के। पुलिस ने कहा कि यह घटना तब सामने आई जब सीसीटीवी फुटेज में महिला को अदालत के कमरे के अंदर यह कार्य करते हुए कैद किया गया। सीसीटीवी फुटेज में महिला को जज की कुर्सी पर जादुई सफेद सरसों के बीज छिड़कते हुए देखा गया। अदालत के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नेत्रा द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई, जिसके बाद आरोपित को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि महिला के खिलाफ कर्नाटक प्रिवेंशन एंड एराडिकेशन आफ इनह्यूमन ईविल प्रैक्टिसेज एंड ब्लैक मैजिक एक्ट, 2017 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने महिला को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले की आगे की जांच जारी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

यूएन में भारत की दो-टूक: 80 साल पुरानी व्यवस्था बदलने की उठाई मांग, कहा- सुरक्षा परिषद में अब सुधार जरूरी

न्यूयॉर्क, एजेंसी। भारत ने मंगलवार (स्थानीय समय) को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में व्यापक सुधारों के लिए अपनी मांग दोहराई। इसके साथ ही बहुपक्षवाद को भविष्य के लिए उपयुक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार, महासभा को पुनर्जीवित करने और आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) की भूमिका को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

राजदूत हरीश परवथानेनी ने क्या कहा: भविष्य के लिए समझौते की समीक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा की अनौपचारिक बैठक के दौरान बहुपक्षवाद को भविष्य के अनुरूप बनाना' विषय पर आयोजित मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश परवथानेनी ने कहा, 'भारत के लिए, बहुपक्षवाद को भविष्य के अनुरूप बनाने की शुरुआत यह

सुनिश्चित करने से होती है कि वैश्विक संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करें।

उन्होंने आगे कहा कि यह सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार, महासभा के पुनरुद्धार और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों आयामों में सतत विकास को आगे बढ़ाने में ईसीओएसओसी की मजबूत भूमिका की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।'

संघर्षो को लेकर क्या कहा: उन्होंने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र के बारे में जनता की धारणा हाल के दिनों में प्रतिकूल रूप से बदल गई है, जिसका मुख्य कारण विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों में सुरक्षा परिषद की सार्थक हस्तक्षेप करने में असमर्थता है। सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी के बीच मानवीय पीड़ा को समाप्त करने में अप्रभावी रही है। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मूल सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सवालों के घेरे में आ गया है।'

परिषद की कमियां का क्या कारण: उन्होंने तर्क दिया कि परिषद की कमियां इसकी पुरानी संरचना के कारण हैं। उन्होंने कहा, 'सुरक्षा परिषद की कमियों का मूल कारण स्पष्ट है। 1940 के दशक के लिए बनाई गई अस्सी साल पुरानी संरचना समकालीन चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ है। एक संगठन के रूप में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने में कोई खास प्रगति नहीं कर पाया है। अब तक की चर्चाएं आईएनजी ढांचे के तहत तैयार बयानों के अंतहीन चक्र तक ही सीमित रही हैं।

थाइलैंड में भारतीयों के लिए बिना वीजा के एंट्री जारी, लेकिन एक शर्त; पूरा मामला क्या

बैंकाक, एजेंसी। थाइलैंड में भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा एंट्री मिलती रहेगी। हालांकि इसमें एक बदलाव भी किया गया है। बिना वीजा के भारतीय थाइलैंड में अधिकतम 30 दिन तक ही रुक पाएंगे। यह वजह, थाई सरकार ने एक खास वजह से लिया है। असल में भारतीयों के वीजा-फ्री एंट्री पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव के बाद से भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। बता दें कि थाइलैंड के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। बड़ी संख्या में भारतीय थाइलैंड घूमने के लिए जाते हैं।

इसलिए लिया गया फैसला: थाइलैंड कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी साप्ताहिक बैठक में भारतीय यात्रियों के लिए 30 दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दे दी। पर्यटन मंत्री सुरसक पंचरोएनवोराकुल ने कहाकि इस कदम का उद्देश्य भारतीय पर्यटकों के लिए चीजों को आसान करना है। इससे देश के पर्यटन उद्योग को भी सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने कहाकि इसलिए कैबिनेट ने भारतीय पर्यटकों के लिहाज से 30 दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दी। यह थाइलैंड के लिए एक बड़ा बाजार हैं। साथ ही पर्यटन मंत्री ने यह भी कहाकि अगर भविष्य में इस कदम से कोई समस्या आती है, तो सरकार इसकी समीक्षा कर सकती है।

पहले क्या था प्रावधान: भारतीय यात्रियों को फिलहाल बिना वीजा के थाइलैंड में 60 दिनों तक रहने की अनुमति है। लेकिन मई में थाई कैबिनेट द्वारा वीजा-मुक्त देशों की सूची को 93 से घटाकर 54 करने और 30 दिन की अवधि तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद यह पॉलिसी खत्म होने

वाली थी। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी तक लागू नहीं हुआ है। पर्यटन मंत्री के अनुसार, इस घोषणा ने भारतीय यात्रियों के बीच भ्रम पैदा कर दिया और यहां से थाइलैंड आने वालों की संख्या काफी कम हो गई। भारत इस साल चीन और मलेशिया के बाद थाईलैंड के लिए तीसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट सोर्स है।

कुछ अन्य देशों को भी छूट: भारत के साथ-साथ, थाइलैंड ने क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, माल्टा और मालदीव के यात्रियों के लिए भी 30-दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दी है। यह जानकारी डिप्टी सरकारी प्रवक्ता प्लॉयटाले लक्समीसांगचन ने दी। इस नए फैसले के बाद 30-दिन की वीजा-फ्री एंट्री के लिए योग्य देशों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इसमें सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देश भी शामिल हैं। प्लॉयटाले ने कहा कि अपडेट की गई नीति थाई पासपोर्ट धारकों के लिए शेंगेन वीजा छूट हासिल करने के थाई प्रयासों को भी समर्थन दे सकती है।

चंडीगढ़ में मतदाता सूची का बड़ा शुद्धिकरण, 66 हजार से ज्यादा वोटर्स के नाम कटेंगे; 21 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट

चंडीगढ़, एजेंसी। यूटी चंडीगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो गया है। निर्वाचन विभाग के अनुसार, कुल 5,16,427 पंजीकृत मतदाताओं में से 3,80,147 मतदाताओं का सफलतापूर्वक मैपिंग कर दी गई है। वहीं 69,484 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) तो जमा कर दिए हैं, लेकिन उनका मैपिंग कार्य अभी पूरा होना बाकी है। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 66,681 मतदाताओं ने निर्धारित समय सीमा तक अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किए। ऐसे मतदाताओं के नाम 21 जुलाई को जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। एसआईआर के दौरान यह भी सामने आया कि 3,521 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 43,878 मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 12,886 मतदाता अनुपस्थित मिले, जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म निर्वाचन विभाग को प्राप्त नहीं हुए।

निर्वाचन विभाग 21 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित करेगा: अब निर्वाचन विभाग 21 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इसके बाद मतदाताओं से दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी, ताकि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा सके और आवश्यक संशोधन किए जा सकें। इसी बीच, एसआईआर के तीसरे चरण के तहत मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी (आईएएस) 15 जुलाई को सुबह 10:45 बजे सेक्टर-18 स्थित निर्वाचन विभाग कार्यालय में प्रेस वार्ता करेंगी। इस दौरान मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और अगले चरण की प्रक्रिया की जानकारी साझा किए जाने की संभावना है।

हिरासत में दिव्यांग व्यक्ति की मौत के बाद वार्डन गिरफ्तार, शरीर पर मिले 19 चोटों के निशान

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की एक सब-जेल में एक विचाराधीन कैदी की मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पोस्टमार्टम में कैदी के शरीर पर चोट के 19 निशान मिलने के बाद एक जेल वार्डन को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने हिरासत में हिंसा के आरोपों और एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय सबरी बर्मन के रूप में हुई है, जो कन्याकुमारी जिले के दक्षिण थामराईकुलम के पास ईथांगडु का रहने वाला एक दिव्यांग व्यक्ति था। 9 जुलाई को दक्षिण थामराईकुलम पुलिस ने उसे गुटखा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मेडिकल जांच के बाद उसे नागरकोइल सब-जेल में एक विचाराधीन कैदी के तौर पर रखा गया था। सोमवार सुबह जेल के अंदर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए असारीपल्लम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया।

पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा: 13 जुलाई को सबरी बर्मन के रिश्तेदार अस्पताल में इकट्ठा हुए और आरोप लगाया कि जेल के अंदर उसे पीट-पीटकर मार डाला गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और स्पष्ट किया कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, वे शव स्वीकार नहीं करेंगे। जानकारी के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्मन के शरीर पर चोट के 19 निशान पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच के आधार पर, पुलिस ने इस मामले में ग्रेड 1 जेल वार्डन जगन को गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया, 'हम मामले की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह मामला जेल के अंदर हुई किसी घटना से जुड़ा प्रतीत होता है।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से मांगा गया जवाब

इस मामले ने राज्य में एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। मुख्य विपक्षी दल डीएमके सहित अन्य पार्टियों ने कथित कस्टोडियल डेथ को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मांग की है कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय इस घटना का जवाब दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग का प्रभार संभालने वाले व्यक्ति को हिरासत में हुई इस मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने इस घटना में कथित तौर पर शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सबरी बर्मन की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। स्टालिन ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बर्मन और उनके परिवार को न्याय मिले।

हिमाचल में लॉटरी से तय आय होगी दोगुनी, नए नियमों के तहत टेंडर जल्द

शिमला, एजेंसी। हिमाचल सरकार ने लॉटरी के संचालन से होने वाली आय बढ़ाने के लिए नियमों में अहम बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर राज्य कोषागार एवं लॉटरी विभाग ने संशोधित प्रस्ताव दोबारा मंजूरी के लिए भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही अगले एक सप्ताह के भीतर लॉटरी संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। नए नियमों के तहत सरकार की सुनिश्चित आय पहले प्रस्तावित तीन करोड़ रुपये से बढ़ाकर छह करोड़ रुपये कर दी गई है। साथ ही टेंडर की शर्तों में भी बदलाव किया गया है, जिससे सरकार का राजस्व पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। विभाग का अनुमान है कि एक वित्तीय वर्ष में लॉटरी से राज्य सरकार को अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है। लॉटरी विभाग ने संशोधित फाइल अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है। मंजूरी के बाद संचालन के इच्छुक कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल वापस आने और

नियमों में संशोधन के कारण प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है, लेकिन सरकार का मानना है कि नए प्रविधान राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे। प्रदेश में वर्ष 1999 में लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त 2025 में 27 वर्ष बाद इसे दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया था। अब संशोधित नियमों के साथ इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।

ईरान पर अमेरिका का बड़ा आर्थिक प्रहार, तेल निर्यात नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक ठिकाने बैन

वाशिंगटन, एजेंसी। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक हमलों को और तेज कर दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग के 'ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल' (ओएफएसी) ने ईरान के अवैध तेल परिवहन और प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले एक बड़े नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया है। इस कार्रवाई के तहत ईरान के ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गज मोहम्मद हुसैन शमखानी के नियंत्रण वाले समुद्री व्यापार नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक लोगों, कंपनियों और जहाजों को प्रतिबंधित सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाल दिया गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों और बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।प्रतिबंधों के दायरे में कौन-कौन आया हः "अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा घोषित इन दंडात्मक उपायों में मुख्य रूप से मोहम्मद हुसैन शमखानी के व्यापक समुद्री व्यापार तंत्र को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई के अंतर्गत कुलः छह लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जिनमें असगर अघिली देहकोर्डी और बेहजाद मोघदास जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।24 कॉरपोरेट कंपनियों और 20 समुद्री जहाजों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैंः अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ये सभी आरोपी वित्तीय ब्रोकरों, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, समुद्री प्रबंधकों और विदेशों में स्थित शेल कंपनियों के एक बेहद जटिल नेटवर्क के जरिए व्यापारिक प्रतिबंधों को बाईपास कर रहे थे। इस कार्रवाई के बाद, इन प्रतिबंधित पक्षों की अमेरिकी कानूनी अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्तियों या कानूनी हितों को

तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है।

अमेरिका ने यह सख्त कदम क्यों उठाया है: अमेरिकी प्रशासन का साफ तौर पर मानना है कि ईरान का यह अवैध तेल नेटवर्क उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार, 'ईरानी शासन धोखे और फरेब पर जीवित है, और शमखानी का यह नेटवर्क उसके सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाले इंजनों में से एक है।' बेसेंट ने जोर देकर कहा कि इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य उस वित्तीय जीवन रेखा को काटना है जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को हवा देती है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमले बढ़े हैं, जिसका आरोप वाशिंगटन ने सीधे तौर पर तेहरान पर लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि यह कार्रवाई शमखानी के अवैध शिपिंग और प्रतिबंधों से बचने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तैयार की गई है, जिसके पैसे से व्यापारिक जहाजों पर हमलों की फंडिंग की जाती थी।

वित्तीय तंत्र पर चोट

शेल कंपनियों और प्रॉक्सी सेटअप का भंडाफोड़ होने से ईरान के लिए अपने तेल को विदेशी बाजारों में बेचना और उसका पैसा वापस तेहरान लाना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

ऊर्जा बाजार में हलचल

ईरान के तेल शिपिंग नेटवर्क पर सीधी चोट से वैश्विक तेल आपूर्ति और इसकी कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।सुरक्षा और तनाव : होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी सेना और ईरान के बीच तनाव और गहरा सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण गलियारा प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी।

अब आगे क्या हो सकता है

वाशिंगटन की इस चौतरफा कार्रवाई से यह साफ है कि वह ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाने की नीति पर कायम रहेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, प्रतिबंधित नेटवर्क में ईरानी नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिक और विदेशी कंपनियां भी शामिल थीं, जो इस अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रही थीं। अब देखना यह होगा कि इस कड़े आर्थिक प्रहार के बाद ईरान की क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या इससे होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है या फिर तनाव और अधिक भड़कता है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डांगा का लोकार्पण, ग्रामीणों को मिली बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात

विधायक कुँवर सिंह टेकाम बोले- अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए धौहनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डांगा में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण बुधवार को विधायक कुँवर सिंह टेकाम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रारंभ होने से डांगा सहित आसपास के अनेक गांवों के लोगों को अब स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक

कुँवर सिंह टेकाम ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है विधायक ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डांगा के शुरू होने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को समय पर उपचार, जांच, दवाइयां, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं अब अपने क्षेत्र में ही मिल सकेंगी पहले जहां ग्रामीणों को सामान्य उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था वहीं अब उन्हें स्थानीय स्तर पर ही स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा इससे ग्रामीणों के समय और आर्थिक संसाधनों दोनों की बचत होगी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का इलाज करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह स्वस्थ और विकसित समाज की नींव है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे पूरी संवेदनशीलता, ईमानदारी और समर्पण के साथ मरीजों की सेवा करें तथा शासन द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करें। विधायक कुँवर सिंह टेकाम ने क्षेत्रवासियों से भी अपील की कि वे स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक रहें और नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, पोषण संबंधी सेवाओं सहित शासन की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में प्रशासन के साथ-साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डांगा में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र में मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं यहां ओपीडी सेवा, सामान्य उपचार, प्रसव सेवाएं, टीकाकरण कार्यक्रम तथा आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सीधी कन्या महाविद्यालय में छात्राओं का प्रदर्शन, 300 से अधिक छात्राओं ने सौंपा ज्ञापन

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में बुधवार को छात्राओं ने विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार के निर्देश पर अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में करीब 300 से अधिक छात्राएं महाविद्यालय परिसर में एकत्रित हुईं और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने ज्ञापन के माध्यम से महाविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं की ओर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित कराया उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी छात्राओं ने बताया कि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम घोषित होने में लगातार देरी हो रही है जिससे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई और अन्य अवसरों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसके अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी के कारण नियमित कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं छात्राओं ने कहा कि प्रायोगिक कक्षाएं भी समय पर संचालित नहीं हो रही हैं जिससे अध्ययन व्यवस्था प्रभावित हो रही है ज्ञापन में छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था, बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों, वर्ष 2025 की लंबित छात्रवृत्ति, बैकलॉग विद्यार्थियों की समस्याओं और आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क लिए जाने जैसे मुद्दे भी उठाए एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार ने कहा कि छात्राओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि महाविद्यालय प्रशासन को छात्राओं की समस्याओं का जल्द समाधान करना चाहिए यदि मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो छात्राओं के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। एनएसयूआई के कोमल सिंह ने कहा कि छात्राओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो महाविद्यालय स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

दुग्ध समृद्धि योजना के तीसरे चरण में घर-घर पहुंच रहा पशुपालन विभाग, वैज्ञानिक पशुपालन से बढ़ेगी दूध उत्पादन और किसानों की आय

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में पशुपालन को अधिक लाभकारी और वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभागीय अधिकारी एवं मैदानी अमला गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन तकनीकों, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी दे रहे हैं। विभाग का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा देकर पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना और पशुपालकों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान पशुपालकों को संतुलित पशु आहार, उन्नत नस्ल विकास, कृत्रिम गर्भाधान, समयबद्ध टीकाकरण तथा सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग के बारे में

विस्तार से जानकारी दी जा रही है अधिकारियों ने बताया कि इस तकनीक के माध्यम से अधिक दुग्ध उत्पादक मादा बछियों की प्राप्ति की संभावना बढ़ती है जिससे भविष्य में डेयरी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है विभागीय टीम पशुपालकों को पशुओं के समुचित स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वच्छ डेयरी पद्धतियों और रोग नियंत्रण के प्रति भी जागरूक कर रही है। अभियान में खुरपका-मुंहपका, लम्पी स्किन रोग जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, नियमित टीकाकरण, कृमिनाशन तथा हरे चारे के उत्पादन और संरक्षण की तकनीकों की जानकारी दी जा रही है साथ ही विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं से अधिक से अधिक पशुपालकों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड सीधी के ग्राम देवछ में विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारियों ने घर-घर जाकर पशुपालकों से संवाद किया और वैज्ञानिक पशुपालन के लाभों की जानकारी दी विशेष रूप से महिला पशुपालकों को सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक के उपयोग, बेहतर नस्ल की मादा संतानों की प्राप्ति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाने के संबंध में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य एवं कृषि स्थायी समिति की सदस्य सरस्वती बहेलिया, ग्राम पंचायत रामगढ़ नंबर-1 के सरपंच सीताराम बहेलिया, पशुपालक महेश प्रसाद केवट सहित बड़ी संख्या में महिला पशुपालक और ग्रामीण उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने पशुपालकों से विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दुग्ध समृद्धि योजना के तीसरे चरण के तहत आगामी दिनों में जिले के सभी विकासखंडों और ग्रामों में इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उद्यान विभाग सीधी ने किराये के वाहन हेतु आमंत्रित की निविदा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, सीधी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासकीय कार्यों के संचालन हेतु किराये के वाहन उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं विभाग द्वारा मासिक दर पर टैक्सी परमिट एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में पंजीकृत वाहन ईंधन सहित उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक वाहन स्वामियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं सहायक संचालक उद्यान ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालयीन कार्यों, विभागीय निरीक्षणों एवं अन्य शासकीय गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए किराये के वाहन की आवश्यकता है इसके लिए इच्छुक वाहन स्वामी निर्धारित प्रारूप में अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं उन्होंने बताया कि वाहन स्वामियों को अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, सीधी में कार्यालयीन समय के दौरान जमा करनी होगी। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निविदा से संबंधित आवश्यक शर्तें, नियम एवं अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, सीधी से प्राप्त की जा सकती है इच्छुक वाहन स्वामी निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सहायक संचालक उद्यान ने सभी पात्र एवं इच्छुक वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय पर निविदा प्रस्तुत करें, ताकि विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप वाहन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी की जा सके।

सीधी में 29 जुलाई को लगेगा युवा संगम, युवाओं को एक ही मंच पर मिलेंगे रोजगार

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय युवा संगम (रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला) का आयोजन 29 जुलाई 2026 को किया जाएगा। यह आयोजन जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला रोजगार कार्यालय, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीधी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जाता है कलेक्टर के आदेशानुसार इस माह का कार्यक्रम 29 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाएगा युवा संगम कार्यक्रम प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय स्वशासी संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, सीधी परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ना है। मेले में देश, प्रदेश एवं स्थानीय स्तर की विभिन्न निजी कंपनियां भाग लेंगी और योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा स्वरोजगार से जुड़े विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे इन स्टॉलों के माध्यम से युवाओं को शासन की स्वरोजगार योजनाओं, ऋण सुविधाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्यमिता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी।

सीधी रेलवे अंडरब्रिज में जल निकासी नहीं ग्रामीणों ने एसडीएम-कलेक्टर से की शिकायत बारिश में जलभराव का डर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले की ग्राम पंचायत भदौरा के शंकरपुर रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन रेलवे अंडरब्रिज में जल निकासी की व्यवस्था न होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है ग्रामीणों ने इस संबंध में कुसमी एसडीएम अजय शर्मा और जिला कलेक्टर से शिकायत की है उन्हें आशंका है कि बारिश के दौरान पानी सीधे उनके घरों में घुस सकता है ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे के ठेकेदार ने अंडरब्रिज का निर्माण तो पूरा कर दिया है लेकिन घरों के सामने पक्की नाली नहीं बनाई इसके अलावा, अंडरब्रिज निर्माण के दौरान घरों के सामने लगभग छह फीट ऊंची दीवार बना दी गई है जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है यदि समय रहते नाली का निर्माण नहीं कराया गया तो बारिश के दिनों में लोगों को गंभीर जलभराव और आवागमन की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

रेलवे विभाग को इस समस्या से अवगत कराया: ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले भी रेलवे विभाग को इस समस्या से अवगत कराया था उस समय विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जल निकासी के लिए पक्की नाली का निर्माण किया जाएगा ताकि किसी को परेशानी न हो हालांकि अब निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के बावजूद नाली का काम शुरू नहीं किया गया है ग्रामीणों का मानना है कि निर्माण पूरा होने के बाद नाली बनाना और भी कठिन हो जाएगा जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी।

एसडीएम के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई: बुधवार को ग्रामीणों ने कुसमी एसडीएम अजय शर्मा के पास पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई शिकायतकर्ताओं में अयोध्या गुप्ता, पार्वती पनिका, बिहारी लाल पनिका, राजकुमार पुनाडिया, राजकुमार गुप्ता, मनोज पुनाडिया, पवन गुप्ता, भारतलाल जायसवाल, शत्रुघ्न जायसवाल, रामप्रसाद जायसवाल, दूधनाथ, श्यामलाल केवट, धर्मेंद्र सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे एसडीएम अजय शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया है।

नशामुक्ति अभियान को मिलेगा जनआंदोलन का स्वरूप, स्कूल-कॉलेजों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक होंगी जागरूकता गतिविधियां

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। नशे के दुष्प्रभावों से समाज को मुक्त करने और युवाओं को नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिले में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत स्कूलों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा अभियान के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि शिक्षण संस्थानों में नशामुक्ति विषयक व्याख्यान, जागरूकता कार्यक्रम, लघु फिल्मों का प्रदर्शन, रील एवं शॉर्ट फिल्म प्रदर्शन सहित विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए चित्रकला, निबंध लेखन, पेंटिंग, स्लोगन, रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा अभियान में विद्यार्थियों के साथ-साथ अभिभावकों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट-गाइड, ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों तथा जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी इनके सहयोग से रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम और नशामुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उद्देश्य यह है कि नशामुक्ति का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे और यह अभियान जनभागीदारी के साथ प्रभावी रूप से संचालित हो अभियान के अंतर्गत प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, बसों, डिजिटल स्क्रीन और अन्य सार्वजनिक परिवहन माध्यमों से नशामुक्ति संबंधी संदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, मानव श्रृंखला, गीत-संगीत और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों से लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर निगरानी रखने तथा स्कूलों के आसपास नशे से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के शौर्य दल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं, ग्राम एवं नगर सुरक्षा समितियां, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से जिलेभर में जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

मेडरा में किसान पाठशाला: महिलाओं को जैविक खेती और आधुनिक धान उत्पादन तकनीकों का मिला प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमपीएसआरएलएम) के अंतर्गत विकासखंड मझौली की ग्राम पंचायत मेडरा में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को प्राकृतिक एवं जैविक खेती की उन्नत तकनीकों से जोड़ना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा कृषि आधारित आजीविका को मजबूत बनाना था किसान पाठशाला के माध्यम से महिला कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने का प्रयास किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षकों द्वारा महिलाओं को जैविक खेती, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक सुंदरलाल तिवारी, प्रियंका पनिका, सूर्यवती कुशवाहा एवं प्रेमवती कुशवाहा ने प्रतिभागियों को विभिन्न कृषि तकनीकों की जानकारी प्रदान की पाठशाला में महिलाओं को अविनाश ब्रह्मास्त्र के निर्माण एवं उपयोग, जैविक खेती की विभिन्न विधियों तथा प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में बताया गया इसके साथ ही धान उत्पादन की आधुनिक तकनीकों जैसे एसआरआई (सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन), एसआरएडब्ल्यू तथा रोपा पद्धति के संबंध में भी विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षकों ने बताया कि इन तकनीकों को अपनाने से कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है प्रशिक्षण के दौरान कृषि विशेषज्ञों ने मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जैविक खाद के उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा खेती में रासायनिक लागत को कम करने के उपायों पर भी चर्चा की। महिलाओं को बताया गया कि जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने से न केवल कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

बरगवां नगर परिषद में पार्षदों का विरोध तेज, खरीदी जांच और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग

पार्षदों ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन, सामग्री सत्यापन, व्यवहार सुधार और बैठने की व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। नगर परिषद बरगवां में पार्षदों का असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। बुधवार को विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को ज्ञापन सौंपकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराया पार्षदों ने परिषद में खरीदी गई सामग्रियों की जांच, आउटसोर्स कर्मचारियों के व्यवहार पर कार्रवाई और जनप्रतिनिधियों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था सहित कई मांगें रखीं पार्षदों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के दौरान नगर परिषद द्वारा की गई विभिन्न खरीदारियों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की गई है पार्षदों का आरोप है कि खरीदी गई सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मात्रा के अनुरूप नहीं हुई है और कई सामग्रियों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल हैं उन्होंने मांग की कि एक जांच समिति गठित कर स्टोर पंजी में दर्ज सामग्री का मौके पर सत्यापन कराया जाए तथा खरीदी प्रक्रिया की पूरी जांच की जाए। पार्षदों ने कहा कि नगर परिषद में जनता के हित से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता आवश्यक है। इसलिए खरीदी गई सामग्रियों की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए ताकि परिषद की कार्यप्रणाली पर विश्वास बना रहे उन्होंने जांच के बाद दोष पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है इसके अलावा पार्षदों ने नगर परिषद में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर भी नाराजगी जताई ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते और कई बार अभद्र भाषा का उपयोग करते पार्षदों का कहना है कि इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मान को ठेस पहुंचती है और आम नागरिकों के कार्य भी प्रभावित होते हैं। ज्ञापन में एक कर्मचारी पर कथित रूप से पांच हजार रुपये की राशि को लेकर विवाद करने और विरोध करने पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया गया है पार्षदों ने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा दोष सिद्ध होने पर उसे परिषद की सेवा से पृथक करने की मांग की है पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा भी उठाया उनका कहना है कि परिषद का कार्यकाल लगभग चार वर्ष पूरा होने को है लेकिन अब तक पार्षदों के लिए अलग से बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है इसके कारण उन्हें जनसमस्याएं सुनने और नागरिकों से संवाद करने में परेशानी होती है। इस संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष प्रमिला बर्मा ने कहा कि पार्षदों द्वारा उठाए गए सभी विषयों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी मामले जांच योग्य हैं उनकी नियमानुसार जांच कराई जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्षदों के बैठने की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे नगर परिषद में पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि परिषद प्रशासन इन मांगों पर किस प्रकार कार्रवाई करता है पार्षदों ने स्पष्ट किया है कि जनहित और परिषद की पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए वे अपनी मांगों को लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे।

पैसे के पीर टीटीई

संपादकीय

सही मायने में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेनों में टीटीई के उस सर्वमान्य भ्रष्ट आचरण को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है, जिसे रेलयात्री कीमत चुकाने के बाद भी कहने में संकोच करते हैं। यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेनों में अक्सर मुश्किल से सफर करने वाले यात्री खाली पड़ी बर्थ अलॉट करा लेते हैं। जिसके एवज में उन्हें टीटीई को किराये के अलावा अतिरिक्त पैसा भी देना पड़ता है। यह चलन देशभर में विभिन्न ट्रेनों में दिखायी देता है। लेकिन अक्सर यात्री अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचकर बात को आई-गई मान लेते हैं। लेकिन जब पैसे देकर अपराधियों को दी गई बर्थ के जरिये चलती ट्रेन में कोई बड़ा अपराध हो जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। दरअसल, जस्टिस राजशेखर मंथा व जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की बेंच साल 2009 में तीस्ता-तोरस एक्सप्रेस में हुई लूट और मौत के मामले में दो दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी। उस दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि टीटीई खाली बर्थ ऐसे बेचते हैं,जैसे बाजार में सब्जियां बिकती हैं। ऐसे में अपराधी खाली बर्थ खरीदकर आरक्षित कोच तक पहुंच बना लेते हैं। वे फिर यात्रियों के साथ घुल-मिलकर उन्हें लूट लेते हैं। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि पैसे लेकर जनरल टिकट वाले यात्रियों को खाली बर्थ देने से अपराधियों को आरक्षित कोच के यात्रियों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। तीस्ता व तोरस केस में भी जो आपराधिक घटना हुई है, उसमें कई टीटीई ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नही निभायी। दरअसल, सत्रह साल पुराने केस में जलपाईगुड़ी से सियालदह जा रही तीस्ता-तोरसा एक्सप्रेस में जनरल टिकट पर सफर कर रहे दो बदमाशों ने टीटीई को पैसे देकर एस-8 कोच में खाली बर्थ ले ली थी। फिर इन्होंने खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर कुछ यात्रियों को बेहोश कर दिया और उनका सामान लूट लिया। घटना में जहरीले पदार्थ से सुनील कुमार दास की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा लंबे समय अस्पताल में उपचार के बाद बच गया था। दरअसल, इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया, लेकिन पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्य न जुटाए जाने के कारण सात साल की जेल के बाद कोर्ट को उन्हें रिहा करना पड़ा। कोर्ट ने टीटीई ही नहीं, पुलिस को भी लापरवाह माना क्योंकि मृतक का विसरा फॉरेंसिक जांच को नहीं भेजा गया। दूसरे यात्री के अस्पताल में उपचार के रिकॉर्ड भी नहीं जुटाए गए। फलतः हत्या के आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। इस घटनाक्रम के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक समेत देशभर के रेलवे अधिकारियों को भेजने को कहा। ताकि पैसे लेकर खाली बर्थ बेचने वाले टीटीई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कदाचार करने वाले रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ अधिकतम कार्रवाई करने को कहा क्योंकि टीटीई की लापरवाही ही ट्रेन में घटे इस अपराध की वजह बनी थी। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति सिर्फ चोरी का शिकार हुआ,लेकिन टीटीई के गैर-जिम्मेदार व्यवहार से उसकी जान चली गई। अदालत ने माना कि ऐसे तमाम मामले सामने नहीं आ पाते हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि रेलवे कर्मचारी ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करें तो यात्रियों का जीवन और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। विडंबना ही है कि अब जब उन्नत तकनीक के जरिये टिकटों के नियमन व सीटों के आवंटन पर पैनी नजर रखना संभव है, तो बर्थ देने में टीटीई की बड़ी भूमिका क्यों है? अक्सर मुश्किलों में सफर कर रहे यात्रियों की मजबूरी का भी टीटीई जमकर फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ी विसंगति यह भी है कि दुनिया के सबसे बड़े रेल-नेटवर्कों में शुमार भारतीय रेलवे नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक हित साधने का माध्यम रहा है। एक समय गठबंधन सरकारों के दौर में रेल मंत्री पद के लिये बड़ी दावेदारी होती थी। अपने चुनाव क्षेत्र व राज्य के लोगों को रेलवे में भर्ती करना प्राथमिकता होती थी, लेकिन चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यशैली में सुधार की दिशा में गंभीर कोशिश होती कभी नजर नहीं आयी।

सोनम वांगचुक का लंबा अनशन अब जीवन पर भारी

कांतिलाल मांडोत

दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है। अनशन के सत्रहवें दिन तक पहुंचते पहुंचते उनका स्वास्थ्य चिंताजनक स्थिति में बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार उनका वजन लगभग साढ़े आठ किलोग्राम कम हो चुका है और लगातार कमजोरी बढ़ रही है। चिकित्सकीय दृष्टि से यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर मानी जाती है। लंबे समय तक भोजन से दूर रहने का असर केवल शरीर के वजन पर ही नहीं पड़ता बल्कि हृदय गुर्दे मांसपेशियों और मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता किसी राजनीतिक मांग से अधिक एक इंसान के जीवन की होनी चाहिए। सोनम वांगचुक देश के जाने माने शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिक्षा पर्यावरण और लद्दाख जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उन्होंने वर्षों तक काम किया है। ऐसे व्यक्ति की आवाज लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने और सरकार से जवाब मांगने का अधिकार है। लेकिन जब विरोध का तरीका स्वयं के जीवन के लिए खतरा बनने लगे तब उस पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक हो जाता है। अनशन भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा का एक पुराना और प्रभावी माध्यम रहा है। महात्मा गांधी से लेकर अनेक सामाजिक नेताओं ने इसका उपयोग नैतिक दबाव बनाने के लिए किया। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि जब किसी अनशनकारी का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगता है तब आंदोलन की दिशा बदलना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। किसी भी आंदोलन का उद्देश्य जीवन की रक्षा करते हुए समाज और व्यवस्था में परिवर्तन लाना होता है न कि स्वयं को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना जहां जीवन ही संकट में पड़ जाए। वर्तमान समय में सोनम वांगचुक के समर्थन में कई विपक्षी नेताओं और फिल्मी हस्तियों ने बयान दिए हैं। उनसे अनशन समाप्त करने की अपील भी की गई है। दूसरी ओर सरकार पर संवेदनहीन होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में यह भी दिखाई देता है कि राजनीतिक दल अपने अपने दृष्टिकोण से इस मुद्दे को प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्ता पक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है जबकि विपक्ष सरकार को घेरने का अवसर तलाश रहा है। यही वह बिंदु है जहां सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है। इसलिए यह मान लेना उचित नहीं होगा कि हर राजनीतिक बयान केवल अनशनकारी के स्वास्थ्य की चिंता से प्रेरित है। विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है और सरकार अपने स्तर पर जवाब दे रही है। लेकिन इस राजनीतिक संघर्ष के बीच सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी का हो सकता है तो वह स्वयं सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य है। वास्तविकता यह है कि यदि उनकी तबीयत और अधिक बिगड़ती है तो सबसे बड़ी कीमत उन्हें और उनके परिवार को चुकानी पड़ेगी। राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ जाएंगे लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता का स्वास्थ्य और जीवन वापस नहीं लौटाया जा सकता। इसलिए यह समय भावनात्मक निर्णयों से अधिक व्यावहारिक सोच का है। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता तेजी से कम होती है। मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। रक्तचाप और शुगर का संतुलन बिगड़ सकता है। हृदय की धड़कन पर भी असर पड़ सकता है। यदि समय रहते चिकित्सा और पोषण नहीं मिले तो स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए डॉक्टर भी आमतौर पर लंबे आमरण अनशन को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण मानते हैं। सोनम वांगचुक यदि अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखना चाहते हैं तो उसके अनेक लोकतांत्रिक विकल्प उपलब्ध हैं। जनसभाएं की जा सकती हैं। देशव्यापी जनजागरण अभियान चलाया जा सकता है। अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित किया जा सकता है। संसद सदस्यों और विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन जुटाया जा सकता है।

भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार का तात्कालिक समय आया

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने या देने तक सीमित अपराध नहीं है,बल्कि यह लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था न्याय व्यवस्था और नागरिकों के विश्वास को भीतर से खोखला करने वाली ऐसी दीमक है जो धीरे- धीरे पूरे शासन तंत्र को कमजोर कर देती है। यदि कैंसर शरीर को अंदर से नष्ट करता है,तो भ्रष्टाचार राष्ट्र की संस्थाओं, नीतियों और नैतिक मूल्यों को उसी प्रकार क्षीण करता है।भारत का आम नागरिक जन्म प्रमाण पत्र से लेकर भूमि रिकॉर्ड, पुलिस, स्थानीय निकाय, कराधान, लाइसेंस, निर्माण अनुमति और अनेक सरकारी सेवाओं तक कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की पीड़ा का अनुभव करता है।कई लोग इसे चाय-पानी कहकर सामान्य मान लेते हैं, जबकि यही छोटी-छोटी रिश्वतें आगे चलकर बड़े भ्रष्टाचार की जड़ बन जाती हैं।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र अधिवक्ता होने के नाते जनता के बीच यह जनजागरण करना चाहूंगा क़ि आज आवश्यकता केवल भ्रष्टाचार की शिकायत करने की नहीं,बल्कि उसे सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बनाने की है।अब ऐसे समय में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक़ (सीपीआई) 2026 भारत सहित पूरी दुनियाँ के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। यह रिपोर्ट भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है।रिपोर्ट के अनुसार भारत 39 अंकों के साथ 91वें स्थान पर है। विशेष बात यह है कि 0 अंक का अर्थ अत्यधिक भ्रष्ट व्यवस्था तथा 100 अंक का अर्थ अत्यंत स्वच्छ और पारदर्शी शासन व्यवस्था है, भारत में बहुत भ्रष्टाचार है लेकिन मैं इस रिपोर्ट को देखकर हैरान हूं कि भारत में इतनी बड़ी लेवल पर भ्रष्टाचारी है,मैंने सोचा भी नहीं था यानें अब सारी जनता समझ रही है कि,यह स्थिति भारत की प्रतिष्ठा पर आघात व विकास में बहुत बड़ी बाधा है?यह रिपोर्ट केवल किसी देश की रैंकिंग नहीं बताती,बल्कि यह उस देश की प्रशासनिक विश्वसनीयता,निवेश वातावरण, शासन की गुणवत्ता और संस्थागत पारदर्शिता का वैश्विक संकेतक भी मानी जाती है।किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह केवल अंक या स्थान का प्रश्न नहीं,बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, निवेशकों के विश्वास और नागरिकों की उम्मीदों का भी विषय है।

साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को समझने की करें तो, दुनियाँ के सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक सूचकांकों में से एक है।इसे हर वर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा को 0 से 100 के पैमाने पर मापती है। 0 अंक का अर्थ अत्यधिक भ्रष्ट व्यवस्था तथा 100 अंक का अर्थ अत्यंत स्वच्छ और पारदर्शी शासन व्यवस्था है। इस सूचकांक की

विशेषता यह है कि यह किसी एक संस्था की राय पर आधारित नहीं होता, बल्कि विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ), एशियाई विकास बैंक सहित लगभग 13 स्वतंत्र वैश्विक स्त्रोतों और विशेषज्ञों के आकलन को समाहित करता है। इसलिए इसकी विश्वसनीयता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जाती है।

साथियों बात कर हम वर्ष 2026 की रिपोर्ट की करें तो इसमें वैश्विक तस्वीर चिंता पैदा करने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार दुनियाँ के दो-तिहाई से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम है,अर्थात अधिकांश देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार गंभीर चुनौती बना हुआ है। यह स्पष्ट संकेत है कि भ्रष्टाचार केवल विकासशील देशों की समस्या नहीं, बल्कि विकसित देशों के लिए भी सतत चुनौती है।हालांकि कुछ देशों ने अपने मजबूत संस्थागत ढांचे, पारदर्शी प्रशासन और कठोर जवाबदेही व्यवस्था के कारण उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।इस वर्ष भी डेनमार्क 89 अंकों के साथ सबसे स्वच्छ देशों में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद फिनलैंड, न्यूज़ीलैंड और नॉर्वे जैसे देश हैं। इन देशों की सफलता का आधार केवल कठोर कानून नहीं,बल्कि मजबूत संस्थाएं,पारदर्शी सरकारी प्रक्रियाएं,स्वतंत्र न्यायपालिका,प्रभावी मीडिया, नागरिक सहभागिता और राजनीतिक ईमानदारी है।दूसरी ओर दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला सबसे अधिक भ्रष्ट देशों में शामिल हैं, जहां राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थाएं और प्रशासनिक विफलता ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

साथियों, भारत की स्थिति इस रिपोर्ट में विशेष चर्चा का विषय बनी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 39 अंकों के साथ 91वें स्थान पर है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि भारत ने डिजिटल प्रशासन,प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) आधार आधारित सेवाओं,सरकारी खरीद में डिजिटलीकरण तथा कई प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से कुछ सकारात्मक प्रगति अवश्य की है,किंतु सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी, प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे अब भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं।भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विदेशी निवेश आकर्षित करने, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने,डिजिटल अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल आर्थिक सुधार पर्याप्त नहीं होंगे। निवेशक केवल बाजार का आकार नहीं देखते, बल्कि वे यह भी देखते हैं कि किसी देश में कानून का शासन कितना मजबूत है, अनुबंधों का पालन कितना प्रभावी है और भ्रष्टाचार का स्तर कितना कम है। इसलिए भ्रष्टाचार का प्रश्न सीधे आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है।

साथियों, भारत में भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं। छोटे स्तर पर सरकारी कार्यालयों में सुविधा शुल्क, भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर, पुलिस या स्थानीय प्रशासन में रिश्वत,ठेकों में अनियमितताएं, सरकारी खरीद में पक्षपात, कर चोरी के लिए मिलीभगत, लाइसेंस और परमिट में अवैध भुगतान जैसी समस्याएं आज भी व्यापक रूप से चर्चा में रहती हैं।बड़े स्तर पर राजनीतिक वित्तपोषण, सार्वजनिक परियोजनाओं में लागत वृद्धि, प्रभाव का दुरुपयोग और सत्ता तथा व्यवसाय के बीच अपारदर्शी संबंध भी चिंता का विषय हैं।एक गंभीर सामाजिक समस्या यह भी है कि भ्रष्टाचार को अनेक लोग व्यवस्था का सामान्य हिस्सा मान चुके हैं। ÷काम जल्दी हो जाए÷ या ÷बिना परेशानी के काम निकल जाए÷ जैसी मानसिकता भ्रष्टाचार कोबढ़ावा देती है। जब रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों इसे सामान्य व्यवहार मान लेते हैं, तब कानून भी सीमित प्रभाव छोड़ता है। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे बड़ा संघर्ष केवल सरकारी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है।

साथियों, हाल के वर्षों में भारत ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी),जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्किटप्लेस), ऑनलाइन टेंडर प्रणाली,आधार आधारित सत्यापन, आयकर और जीएसटी का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवा वितरण और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन ने भ्रष्टाचार की अनेक संभावनाओं को कम किया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों तक बिना बिचौलियों के सरकारी सहायता पहुंचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।फिर भी केवल तकनीक समाधान नहीं है। यदि संस्थागत जवाबदेही कमजोर रहे, शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई न हो, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठें और दोषियों को शीघ्र दंड न मिले, तो तकनीकी सुधार भी सीमित प्रभाव ही छोड़ेंगे। इसलिए तकनीक के साथ मजबूत संस्थागत सुधार अनिवार्य हैं।

साथियों, राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता आज सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक हैं, किंतु चुनावी वित्तपोषण यदि अपारदर्शी रहेगा तो नीति निर्माण पर निजी हितों का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों की आय, चुनावी चंदे और व्यय की पारदर्शिता लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।स्वतंत्र संस्थाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग,नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सूचना आयोग, न्यायपालिका, सतर्कता तंत्र और स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र के प्रहरी हैं। यदि ये संस्थाएं निष्पक्ष, स्वतंत्र और संसाधन- संपन्न हों तो भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।सूचना का अधिकार (आरटीआई) ने भारत में पारदर्शिता बढ़ाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।अनेक घोटाले, अनियमितताएं और प्रशासनिक कमियां इसी कानून के माध्यम से सामने आई। इसलिए पारदर्शिता और सूचना तक नागरिकों की पहुंच को और मजबूत करना समय की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई नागरिक रिश्वत देने के बजाय शिकायत दर्ज कराए, डिजिटल पोर्टल का उपयोग करे, सबूत सुरक्षित रखे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करे, तो व्यवस्था पर सकारात्मक दबाव बनता है। हर शिकायत तत्काल परिणाम नहीं देती, लेकिन सामूहिक नागरिक भागीदारी व्यवस्था में परिवर्तन का आधार बनती है।

साथियों,विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नैतिक शिक्षा, ईमानदारी, सार्वजनिक जीवन के मूल्यों और संवैधानिक कर्तव्यों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। भविष्य की पीढ़ी यदि ईमानदारी को सफलता का आधार मानेगी,तभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध दीर्घकालिक परिवर्तन संभव होगा।कॉर्पोरेट क्षेत्र की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। रिश्वत देकर अनुबंध प्राप्त करना, कर चोरी, फर्जी बिलिंग या अनुचित प्रभाव का उपयोग करना भी भ्रष्टाचार का हिस्सा है। इसलिए मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस,स्वतंत्र ऑडिट, व्हिसलब्लोअर सुरक्षा और नैतिक व्यावसायिक आचरण आवश्यक हैं।

साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे अधिक नुकसान गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे उद्यमियों को होता है। जिनके पास संसाधन कम होते हैं,वे रिश्वत देने में अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। परिणामस्वरूप सामाजिक असमानता और बढ़ती है। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष वास्तव में सामाजिक न्याय का भी संघर्ष है।भारत यदि विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है,तो उसेआर्थिक विकास के साथ सुशासन को भी समान प्राथमिकता देनी होगी। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा केवल उत्पादन, तकनीक और निवेश से नहीं,बल्कि पारदर्शिता,कानून के शासन और संस्थागत विश्वसनीयता से भी तय होती है।

साथियों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2026 रिपोर्ट भारत के लिए निराशा का नहीं,बल्कि आत्ममंथन और सुधार का अवसर है। 91वीं रैंक यह संदेश देती है कि अभी लंबी यात्रा शेष है। यदि हम डिजिटल प्रशासन काविस्तार करें,शिकायत निवारण को प्रभावी बनाएं, स्वतंत्रसंस्थाओं को मजबूत करें,राजनीतिक वित्तपोषण में पूर्णपारदर्शिता लाएं, न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करें और नागरिकों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध सक्रिय भागीदार बनाएं, तो भारत की स्थिति आने वाले वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बेहतर हो सकती है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन, मीडिया, उद्योग, नागरिक समाज और प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। जब तक रिश्वत देने वाला यह नहीं कहेगा कि ÷मैं सुविधा शुल्क नहीं दूंगा÷,तब तक रिश्वत लेने वाला भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए समय की मांग है कि भ्रष्टाचार को सुविधा नहीं, अपराध माना जाए; मौन नहीं, शिकायत की जाए; समझौता नहीं, प्रतिरोध किया जाए। तभी भारत वैश्विक मंच पर केवल आर्थिक महाशक्ति ही नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और नैतिक नेतृत्व का भी उदाहरण बन सकेगा।

पश्चिम एशिया में बदलता शक्ति-संतुलन और नई कूटनीतिक चुनौतियाँ

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर पश्चिम एशिया को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ले आया है। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियों, जवाबी कार्रवाइयों और कूटनीतिक टकराव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह विवाद अब केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है। इसके साथ ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और महाशक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसे कई आयाम जुड़ चुके हैं। यही कारण है कि पश्चिम एशिया में होने वाली हर घटना का प्रभाव अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर पड़ता है।

राज कुमार सिन्हा

अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही अधिकतम दबाव की नीति और ईरान की प्रतिरोध रणनीति के बीच टकराव लगातार गहराता गया है। हालिया घटनाक्रम में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध सैन्य और रणनीतिक कदम तेज किए हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार संघर्षविराम की कोशिशों के बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ईरान ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह बाहरी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका अपने क्षेत्रीय हितों और सहयोगी देशों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। इससे पश्चिम एशिया में अस्थिरता की आशंका लगातार बनी हुई है। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू होर्मुज जलडमरूमध्य है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। यदि इस मार्ग पर सैन्य तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, तो उसका सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियाँ भी समय-समय पर चेतावनी देती रही हैं कि इस क्षेत्र में किसी बड़े सैन्य टकराव से तेल की आपूर्ति और कीमतों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए होर्मुज केवल क्षेत्रीय सामरिक महत्व का प्रश्न नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता का भी विषय है। इसी बीच पश्चिम एशिया में महाशक्तियों की सक्रियता भी बढ़ी है। रूस और चीन ने विभिन्न स्तरों पर ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। चीन ऊर्जा सहयोग, निवेश और आर्थिक संपर्कों के माध्यम से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, जबकि रूस रक्षा और सामरिक सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। इन घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया है कि पश्चिम एशिया अब केवल अमेरिकी प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में नहीं देखा जा सकता। यहाँ शक्ति-संतुलन धीरे-धीरे अधिक बहुध्रुवीय स्वरूप ग्रहण कर रहा है। इस बदलते परिदृश्य का प्रभाव क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर भी दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और अन्य खाड़ी देश अब केवल एक महाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित कूटनीतिक संबंध विकसित करने की नीति अपना रहे हैं। वे अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा संबंध बनाए रखते हुए चीन, रूस और ईरान के साथ भी संवाद बढ़ा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया की राजनीति अब पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल और बहुस्तरीय हो चुकी है। पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्रीय राजनीति अब केवल सैन्य शक्ति से संचालित नहीं होगी। ऊर्जा संसाधनों, समुद्री व्यापार मार्गों, आर्थिक प्रतिबंधों, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण जैसे नए कारक कूटनीतिक निर्णयों के केंद्र में आ चुके हैं। यही कारण है कि क्षेत्र के अधिकांश देश अपनी विदेश नीति में अधिक व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण अपना रहे हैं। चीन की भूमिका इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। बीते कुछ वर्षों में उसने ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से पश्चिम एशिया में अपनी आर्थिक उपस्थिति लगातार बढ़ाई है। ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों की बहाली में उसकी मध्यस्थता ने यह संकेत दिया कि बीजिंग अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि कूटनीतिक भूमिका निभाने की भी क्षमता रखता है। दूसरी ओर, रूस रक्षा सहयोग, ऊर्जा समन्वय और रणनीतिक साझेदारी के जरिए क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। ब्रिक्स के विस्तार और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार जैसे प्रयास भी पश्चिमी प्रतिबंधों के विकल्प तलाशने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। इन घटनाक्रमों का अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका का प्रभाव समाप्त हो गया है। अमेरिका अब भी पश्चिम एशिया की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति है और उसके सुरक्षा गठबंधन क्षेत्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब उसे ऐसे क्षेत्र का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ अन्य शक्तियाँ भी प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। परिणामस्वरूप, एकध्रुवीय व्यवस्था की जगह बहुध्रुवीय शक्ति-संतुलन का स्वरूप उभरता दिखाई दे रहा है। यूरोपीय देशों के सामने भी नई कूटनीतिक चुनौती है। एक ओर वे अमेरिका के पारंपरिक सुरक्षा सहयोगी हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी ऊर्जा आवश्यकताएँ और व्यापारिक हित उन्हें ईरान तथा खाड़ी देशों के साथ संवाद बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि यूरोपीय कूटनीति में भी टकराव के बजाय संवाद और तनाव कम करने के प्रयासों पर अधिक बल दिया जा रहा है। इन परिस्थितियों में यह समझना आवश्यक है कि पश्चिम एशिया का संकट केवल क्षेत्रीय राजनीति का प्रश्न नहीं है। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार, महँगाई, आपूर्ति श्रृंखलाओं और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी है। आने वाले समय में यह संघर्ष किस दिशा में जाता है, इससे न केवल पश्चिम एशिया बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन की दिशा भी प्रभावित होगी। भारत के लिए यह पूरा घटनाक्रम केवल दूर बैठे दो देशों का संघर्ष नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक हितों और विदेश नीति से सीधे जुड़ा प्रश्न है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है और उसका महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था, महँगाई, ऊर्जा लागत और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ना स्वाभाविक है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पारंपरिक रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने की है। एक ओर उसके अमेरिका, इज़राइल और खाड़ी देशों के साथ मजबूत सामरिक एवं आर्थिक संबंध हैं, तो दूसरी ओर ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और मध्य एशिया तक पहुँच जैसे दीर्घकालिक रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत के लिए किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होने के बजाय संतुलित और व्यावहारिक कूटनीति अपनाना ही सबसे उपयुक्त विकल्प दिखाई देता है। वर्तमान परिस्थितियाँ यह भी संकेत देती हैं कि पश्चिम एशिया धीरे-धीरे अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभाव से निकलकर बहुध्रुवीय शक्ति-संतुलन की ओर बढ़ रहा है। चीन आर्थिक निवेश और कूटनीतिक मध्यस्थता के माध्यम से अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है, जबकि रूस रक्षा और सामरिक सहयोग के जरिए क्षेत्रीय समीकरणों में सक्रिय बना हुआ है। खाड़ी देश भी अब केवल सुरक्षा के प्रश्न पर नहीं, बल्कि निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। यह परिवर्तन आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दिशा को गहराई से प्रभावित कर सकता है। हालाँकि यह भी स्पष्ट है कि केवल शक्ति-संतुलन बदलने से क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं होगी। पश्चिम एशिया की जटिल समस्याओं का समाधान सैन्य कार्रवाई से अधिक संवाद, विश्वास-निर्माण और बहुपक्षीय कूटनीति में निहित है।

झुरा जलाशय का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, सिंचाई परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिया जोर

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को बेहतर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सु संतन देवी जांगड़े ने बुधवार को नागपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत हर्रा स्थित झुरा जलाशय तथा निर्माणाधीन सिंचाई नहरों का औचक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित विकास कार्यों की प्रगति, निर्माण गुणवत्ता और परियोजनाओं की उपयोगिता का गहन अवलोकन करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर तकनीकी मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ शीघ्र मिल सके। निरीक्षण के दौरान एसडीएम लिंगराज सिदार, तहसीलदार समीर शर्मा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यपालन अभियंता (प्रभारी) मोती राम सिंह, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एन.सी. सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे कलेक्टर ने अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उपयोगिता के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर ने सबसे पहले झुरा जलाशय का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने जल संग्रहण क्षमता, जलाशय की वर्तमान स्थिति, रखरखाव व्यवस्था तथा सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की स्थिति की समीक्षा की अधिकारियों ने उन्हें जलाशय की क्षमता और इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की जानकारी दी कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जलाशय का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए ताकि पूरे सिंचाई सत्र के दौरान किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सके उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए जलाशय की क्षमता बढ़ाने के लिए रीसेक्शन (पुनर्सुधार) का प्रस्ताव तत्काल तैयार कर शासन को भेजा जाए जिससे अधिक जल संग्रहण संभव हो सके और अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर निर्माणाधीन नहर तक भी पहुंचीं और वहां चल रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2500 मीटर लंबी इस नहर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है परियोजना पूरी होने के बाद हर्रा, लाई और नागपुर ग्राम के किसानों को नियमित एवं पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी इससे बड़ी संख्या में कृषि भूमि सिंचित होगी जिससे खेती की उत्पादकता बढ़ने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होने की संभावना है। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि नहर निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप किया जाए उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर कार्यों की निगरानी करने तथा किसी भी कमी को तत्काल दूर करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने खेतों में पहुंचकर सिंचाई कर रहे किसान मोहन सिंह से बातचीत की उन्होंने खेती-किसानी की वर्तमान स्थिति, फसलों की प्रगति, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता तथा योजनाओं से किसानों को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली किसान ने बताया कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से खेती पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हुई है और फसलों का उत्पादन भी बेहतर हो रहा है इस पर कलेक्टर ने किसानों से शासन द्वारा संचालित कृषि एवं सिंचाई योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने की अपील की तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया कलेक्टर ने ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को नहरों की नियमित साफ-सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि नहरों में कचरा, प्लास्टिक या अन्य अपशिष्ट पदार्थ डालने से जल प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे किसानों को समय पर सिंचाई का लाभ नहीं मिल पाता उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया ताकि लोग नहरों की स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने लाई से हर्रा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क का भी निरीक्षण किया उन्होंने सड़क निर्माण की प्रगति, उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री तथा गुणवत्ता का परीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क मजबूत, टिकाऊ और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप बनाई जाए।

वीबी-जी-राम-जी एक्ट-2025 पर पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया विशेष जोर

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। विकसित भारत-ग्राम (वीबी-जी-राम-जी) एक्ट-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ में ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रशिक्षण में अधिनियम के नए प्रावधानों, विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) तथा ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वीबी-जी-राम-जी एक्ट-2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, समृद्ध, जल सुरक्षित और सतत विकास के मॉडल के रूप में विकसित करना है इसके लिए पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाबद्ध कार्यों का चयन कर जनभागीदारी के साथ उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना होगा प्रतिभागियों को विकसित ग्राम पंचायत योजना के नौ प्रमुख विकास क्षेत्रों, 60:40 अनुपात में कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया तथा 318 अनुमन्य विकास कार्यों की श्रेणियों की जानकारी दी गई साथ ही जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्धन और आपदा प्रबंधन जैसे चार प्रमुख कार्य क्षेत्रों पर विशेष चर्चा की गई प्रशिक्षण में मोर गांव-मोर पानी अभियान को प्राथमिकता देते हुए वर्षा जल संरक्षण, खेत तालाब, आजीविका डबरी, चेकडैम, रिचार्ज संरचनाओं और जल स्त्रोतों के संरक्षण जैसे कार्यों को व्यापक स्तर पर लागू करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इससे भू-जल स्तर में सुधार होगा और भविष्य में जल संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा।

उपजेल मनेन्द्रगढ़ के निरीक्षण में नहीं मिला कोई विधि से संघर्षरत बालक, किशोर न्याय अधिनियम के पालन की हुई समीक्षा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन और विधि से संघर्षरत बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.) एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त टीम ने मनेन्द्रगढ़ उपजेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह संतोषजनक तथ्य सामने आया कि उपजेल में किसी भी विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध नहीं रखा गया है संयुक्त निरीक्षण दल में किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य मती पुष्पा गुलकरी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सु कोमल सिंह, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सा जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता रामयज्ञ साहू तथा अनिकेत ठाकुर शामिल थे टीम ने उपजेल पहुंचकर जेल प्रबंधन से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और बंदियों से संबंधित अभिलेखों एवं व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपजेल में निरुद्ध बंदियों की संख्या, उनकी श्रेणी तथा विधि से संघर्षरत बालकों की उपलब्धता का विशेष रूप से सत्यापन किया गया जांच में पाया गया कि निरीक्षण के समय उपजेल मनेन्द्रगढ़ में कुल 131 बंदी निरुद्ध थे, लेकिन उनमें कोई भी विधि से संघर्षरत बालक शामिल नहीं था टीम ने अभिलेखों के मिलान और भौतिक सत्यापन के बाद इस स्थिति की पुष्टि की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि भविष्य में यदि किसी विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा में लिया जाता है तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं संबंधित नियमों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जाए ऐसे मामलों में बालक को शीघ्र ही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने तथा उसकी सुरक्षा, अधिकारों और गरिमा का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया गया।

लरकोडा में सार्वजनिक हैंडपंपों का क्लोरीनेशन, स्वच्छ पेयजल के लिए पीएचई विभाग का विशेष अभियान

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम लरकोडा में ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग ने सार्वजनिक हैंडपंपों का क्लोरीनेशन अभियान चलाया इस अभियान के तहत गांव के सभी सार्वजनिक हैंडपंपों में निर्धारित मानकों के अनुरूप क्लोरीन का उपयोग कर पेयजल को जीवाणुमुक्त बनाने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसका उद्देश्य जलजनित बीमारियों की रोकथाम के साथ ग्रामीणों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार के निर्देश पर विभाग की तकनीकी टीम और हैंडपंप टेक्नीशियनों ने अभियान संचालित किया। टीम ने प्रत्येक सार्वजनिक हैंडपंप में निर्धारित मानक के अनुसार 30 एमएल क्लोरीन का उपयोग कर क्लोरीनेशन किया इससे पेयजल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया और संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया गया। अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के महत्व, जल स्त्रोतों की नियमित साफ-सफाई और हैंडपंपों के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए भी जागरूक किया। ग्रामीणों से जल स्त्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने, जल संरक्षण अपनाने तथा सामुदायिक सहयोग से पेयजल स्त्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की नई पहल : युवाओं को मिलेगा नि:शुल्क टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण पहल की है बोर्ड द्वारा अगस्त-सितंबर 2026 के दौरान प्रदेश के युवाओं के लिए नि:शुल्क टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का संचालन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट (आईआईटीटीएम), ग्वालियर के सहयोग से किया जाएगा प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रतिभागियों को संस्थान की ओर से प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा जिससे पर्यटन क्षेत्र में उनके लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक ने इस संबंध में सरगुजा संभाग के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं पत्र के अनुसार अंबिकापुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) तथा सूरजपुर जिलों से पात्र युवाओं का चयन कर उनकी जानकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर बोर्ड को भेजी जाएगी पर्यटन क्षेत्र आज देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों, वन संपदा, धार्मिक स्थलों, जनजातीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध राज्य है इसके बावजूद प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइडों की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म बोर्ड ने यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है ताकि स्थानीय युवाओं को पेशेवर प्रशिक्षण देकर पर्यटन उद्योग से जोड़ा जा सके प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पर्यटन प्रबंधन, पर्यटकों से प्रभावी संवाद, स्थानीय इतिहास एवं संस्कृति, पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी, आतिथ्य प्रबंधन, पर्यटक व्यवहार, सुरक्षा मानकों तथा व्यावहारिक गाइडिंग जैसे विषयों का विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा प्रतिभागियों को पर्यटकों के साथ व्यवहार, आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता, स्थानीय पर्यटन स्थलों का प्रभावी परिचय तथा पर्यटन से जुड़े आधुनिक मानकों की भी जानकारी दी जाएगी।

जनदर्शन में गूंजीं जनसमस्याएं, कलेक्टर ने हर आवेदन पर दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंचे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सु संतन देवी जांगड़े ने प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनी तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं

के प्रभावी समाधान का माध्यम है जनदर्शन में अपर कलेक्टर मती नम्रता डोंगरे, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राजस्व, वनाधिकार, भूमि विवाद, राशन, प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सौर ऊर्जा, मुआवजा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े अनेक मामलों पर आवेदन प्राप्त हुए कोटाडोल निवासी छत्रपाल ने नक्शे में त्रुटि सुधार, सकड़ा की भागवती ने वनाधिकार पट्टे में आश्रितों के नाम जोड़ने तथा नेवरी निवासी रामप्रसाद ने वन भूमि का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज कराने की मांग रखी वहीं गिद्धडांड के सोनसाय ने राशन कार्ड निरस्त होने और राशन नहीं मिलने की शिकायत की देवाडांड के अजय कुमार साहू ने लंबित भुगतान दिलाने तथा सलका के राजेंद्र प्रसाद ने आपसी विवाद के समाधान की मांग की। चिरमिरी निवासी मिली जैन ने भूमि संबंधी लंबित प्रकरण, डायवर्सन भूमि विक्रय की अनुमति तथा बकाया भुगतान के शीघ्र निराकरण की मांग की बहरासी के लाल बहादुर ने अवैध पट्टा निरस्त करने, मनेंद्रगढ़ के नईम खान ने तहसील रिकॉर्ड रूम से दस्तावेजों की नकल उपलब्ध कराने और विपिन आर. नायर ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। नवापारा के कई ग्रामीणों ने शासकीय वन भूमि का पट्टा देने की मांग रखी, जबकि अन्य ग्रामीणों ने भूमि एवं पट्टा संबंधी विवादों के समाधान की मांग की।

बंजी में विकास कार्यों का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुधारने के दिए सख्त निर्देश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता और शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सु संतन देवी जांगड़े ने बुधवार को ग्राम पंचायत बंजी का औचक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र, खाद-बीज वितरण व्यवस्था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों सहित विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम लिंगराज सिदार, तहसीलदार सु श्रुति धुर्वे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यपालन अभियंता (प्रभारी) मोती राम सिंह, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एन.सी. सिंह तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सबसे पहले बंजी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने बच्चों को मिलने वाली पोषण सेवाओं, पूरक आहार, साफ-सफाई, उपस्थिति और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण स्तर और कुपोषण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समय पर पहुंचे तथा केंद्रों में स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जाएं इसके बाद कलेक्टर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बंजी पहुंचीं, जहां उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर खाद एवं बीज वितरण व्यवस्था की जानकारी ली किसान शिवरतन, शिवबचन और उमेंद्र सिंह से चर्चा के दौरान उन्होंने खाद और बीज की उपलब्धता, गुणवत्ता तथा वितरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की किसानों ने अपनी आवश्यकताओं और अनुभवों से कलेक्टर को अवगत कराया इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेती के मौसम में किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त खाद और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाएं ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो।

एमसीबी में स्वर्णप्राशन योजना की शुरुआत, कुपोषण मुक्त जिले की ओर बढ़ा बड़ा कदम

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बुधवार से स्वर्णप्राशन योजना की शुरुआत की कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े के मार्गदर्शन में आयुष विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मनेन्द्रगढ़ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंजी में योजना का शुभारंभ किया गया। आयुर्वेद आधारित इस योजना का उद्देश्य बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा कुपोषण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है योजना के पहले चरण में जिले के 722 बच्चों को स्वर्णप्राशन का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

इसकी शुरुआत उत्साहजनक रही और पहले ही दिन 334 बच्चों को स्वर्णप्राशन संस्कार कराया गया। अधिकारियों का मानना है कि यह आंकड़ा अभिभावकों में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा प्रशासन की सक्रिय पहल का सकारात्मक संकेत है। मनेन्द्रगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर सु संतन देवी जांगड़े ने गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वर्णप्राशन संस्कार कराकर अभियान का विधिवत शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ बचपन ही सशक्त समाज की नींव है और कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य, पोषण और जनसहभागिता का समन्वय आवश्यक है उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक माह निर्धारित तिथि पर अपने बच्चों को स्वर्णप्राशन के लिए अवश्य लाएं ताकि योजना का निरंतर लाभ मिल सके कलेक्टर ने कहा कि संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के समन्वित प्रयासों से बच्चों के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार संभव है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिले के सभी विभागों और आम जनता के सहयोग से एमसीबी को कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य अवश्य हासिल किया जाएगा कार्यक्रम में जिला आयुष अधिकारी डॉ. निशांत कुमार अग्रवाल और आयुष चिकित्सक डॉ. पूर्णिमा सिंह ने स्वर्णप्राशन के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में वर्णित स्वर्णप्राशन संस्कार बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने, स्मरण शक्ति और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने, शारीरिक वृद्धि में सहयोग करने तथा मौसम परिवर्तन के दौरान होने वाले संक्रमणों से बचाव में सहायक माना जाता है नियमित रूप से स्वर्णप्राशन कराने से बच्चों का समग्र विकास बेहतर होता है और कुपोषण की रोकथाम में भी मदद मिलती है जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा ने बताया कि मनेन्द्रगढ़ ग्रामीण, मनेन्द्रगढ़ शहरी, झगराखांड, पाराडोल और नागपुर सहित मनेन्द्रगढ़ परियोजना के विभिन्न सेक्टरों के कुल 388 बच्चों को इस चरण में स्वर्णप्राशन कराया जाना प्रस्तावित है इसके बाद जिले के अन्य विकासखंडों में भी चरणबद्ध तरीके से पात्र बच्चों को योजना से जोड़ा जाएगा ताकि अधिक से अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें इसी क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंजी में भी स्वर्णप्राशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में बच्चों को स्वर्णप्राशन संस्कार कराया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यपालन अभियंता मोती राम तथा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता नरेश चन्द्र ने भी बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया और अभिभावकों से बच्चों के संतुलित पोषण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा इस योजना में निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यक्रम में एसडीएम लिंगराज सिदार, तहसीलदार सु श्रुति धुर्वे, परियोजना अधिकारी मती शशि जायसवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा, जिला आयुष अधिकारी डॉ. निशांत कुमार अग्रवाल, आयुष चिकित्सक डॉ. पूर्णिमा सिंह, पर्यवेक्षक मती शिल्पा अग्रवाल एवं मती पूनम सिंह सहित आयुष विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ अभिभावकों को पोषण, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में भी जागरूक किया गया।

महतारी वंदन योजना बनी महिलाओं का आर्थिक संबल

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम भल्लौर की निवासी मती संतोषी भी इस योजना से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी हैं उनका कहना है कि हर महीने मिलने वाली सहायता राशि से घरेलू खर्चों का बोझ कम हुआ है और आर्थिक आत्मविश्वास भी बढ़ा है। संतोषी ने बताया कि उन्हें महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि नियमित रूप से सीधे बैंक खाते में प्राप्त हो रही है अब तक उन्हें 29 किश्तों के माध्यम से कुल 29 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल चुकी है उन्होंने कहा कि यह राशि परिवार के लिए उपयोगी साबित हो रही है और घर की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है उन्होंने बताया कि योजना से प्राप्त राशि का उपयोग वे साग-सब्जी, राशन, घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य छोटे-छोटे खर्चों में करती हैं।

महिला को जहरीले सांप ने तीन बार डसा, झाड़फूंक के बजाय इलाज से बची जान, डॉक्टर ने लगाए 25 इंजेक्शन

मीडिया ऑडीटर, पिपरिया (निप्र)। पिपरिया के झील पिपरिया गांव में सोमवार को एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन पहले उसे झाड़फूंक के लिए ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर पिपरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने समय पर इलाज देकर महिला की जान बचाई। अस्पताल में भर्ती राधाबाई पति सुखराम 37 ने मंगलवार को सोमवार को वह घर के आंगन में काम कर रही थी। तभी करीब पांच फीट लंबे सांप ने उसके दाहिने हाथ में तीन बार डस लिया। डॉ. देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि परिजन महिला को पहले झाड़फूंक करवाने ले गए थे, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी। अस्पताल लाने पर उसे 25 से अधिक एंटी-स्नेक वेनम (ASV) इंजेक्शन लगाए गए, साथ ही ड्रिप और मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी दिए गए। जहर फैलने के कारण महिला का रक्तचाप (BP) 200 तक पहुंच गया था और उसकी आंखें बंद हो गई थीं। डॉ. ठाकुर के अनुसार, करीब डेढ़ घंटे के इलाज के बाद महिला ने आंखें खोलीं। अब उसकी स्थिति में 80 प्रतिशत सुधार है और उसे अगले दो दिनों तक अस्पताल में निगरानी में रखा जाएगा। डॉ. देवेंद्र ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में सांप के काटने पर झाड़फूंक के बजाय तुरंत सरकारी अस्पताल आएं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सांप के काटने का समुचित उपचार उपलब्ध है, जिससे मरीज की जान बचाई जा सकती है।

नकाबपोश बदमाशों ने शराब दुकान में घुसकर मारपीट की, सागर में शॉप के बाहर खड़ी बाइकों में तोड़फोड़ की,

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर में गौरझामर थाना क्षेत्र स्थित शराब दुकान पर आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने सोमवार देर रात हमला कर दिया। हमलावरों ने दुकान में मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की। जिससे तीन कर्मचारी घायल हुए। दुकान के बाहर खड़ी बाइकों में तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वारदात सोमवार रात की है। सामने आए वीडियो में नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सूचना पर गौरझामर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। देवरी एसडीओपी अरुण कुमार ने बताया कि शराब दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट की वारदात सामने आई है। शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाने शराब दुकान संचालक व अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है।

सीहोर में हाईवे पर खड़े डंपर में ट्रक की टक्कर: 8 साल के बच्चे समेत दो की मौत

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर में नेशनल हाईवे-46बी के मिडघाट सेक्शन में बुधवार तड़के करीब 4 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े खराब डंपर में पीछे से आ रहे आइसर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 8 साल के बच्चे समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार, नेशनल हाईवे-46बी पर एक डंपर खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था। उसका चालक वाहन ठीक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आए आइसर ट्रक ने डंपर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया हादसे में प्रदीप (30) निवासी ग्राम बागोली, थाना सांची, जिला रायसेन और राजवीर (8) निवासी परासिया, जिला छिंदवाड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही बुधनी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया और घटनास्थल का मुआयना किया। इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। बुधनी एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि एक वाहन खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था और उसका चालक उसे ठीक कर रहा था। तभी पीछे से आए दूसरे वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में प्रदीप (30) और 8 वर्षीय राजवीर की मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

रायसेन में 15 दिन से बारिश नहीं, धान मुरझाई

खरीफ की बोवनी पर संकट छाया, खेतों में पड़ने लगीं दरारें, किसान बोले पानी नहीं गिरा तो होगा नुकसान

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में मानसून की रफ्तार थमने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआती दौर में अच्छी बारिश के बाद पिछले 15 दिनों से जिले में बारिश नहीं हुई है। इसका सीधा असर खरीफ फसलों की बोवनी और धान की रोपाई पर पड़ा है। जिन किसानों ने समय पर धान की रोपाई कर दी थी, उनकी फसल अब पानी के अभाव में सूखने लगी है, जबकि हजारों हेक्टेयर खेत अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

15 दिन से बारिश नहीं, खेतों में सूखने लगी फसल: जिले में लगातार बारिश नहीं होने से खेतों की नमी खत्म होती जा रही है। धान की पौध मुरझाने लगी है और कई खेतों में मिट्टी फटने से दरारें पड़ गई हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो अब तक की मेहनत और लागत दोनों पर पानी फिर सकता है।

खरीफ बोवनी लक्ष्य से काफी पीछे: कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में खरीफ फसलों की बोवनी का लक्ष्य 3 लाख 93 हजार हेक्टेयर निर्धारित किया है।

अब तक केवल 2 लाख 34 हजार 100 हेक्टेयर में ही बोवनी हो सकी है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 60 प्रतिशत है। बारिश की कमी के कारण बोवनी की रफ्तार लगभग थम गई है।

धान की रोपाई सबसे ज्यादा प्रभावित: रायसेन जिले में धान प्रमुख खरीफ फसल है। इस बार धान की रोपाई का लक्ष्य 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 1 लाख 12 हजार 91 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रोपाई हो पाई है। वहीं सोयाबीन, उड़द, मूंग और अरहर जैसी अन्य फसलों की बुवाई भी अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है।

एक-दो दिन में बारिश नहीं हुई तो बढ़ेगी मुश्किल

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार धान की रोपाई जुलाई के अंत तक की जा सकती है, लेकिन सोयाबीन, उड़द, मूंग और अरहर जैसी फसलों की बुवाई के लिए समय तेजी से निकल रहा है। यदि अगले एक-दो दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई, तो बड़ी संख्या में खेत खाली रह सकते हैं और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

बारिश की कमी के चलते लक्ष्य भी घटाना पड़ा

मानसून की कमजोर शुरुआत और कम बारिश की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने पहले खरीफ बोवनी का लक्ष्य 4 लाख 10 हजार हेक्टेयर रखा था। बाद में इसे घटाकर 3 लाख 93 हजार हेक्टेयर कर दिया गया। इसके बावजूद वर्तमान स्थिति को देखते हुए लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है।

किसानों की बढ़ी चिंता

बारिश की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। महंगे बीज, खाद और खेती की लागत लगाने के बाद अब उनकी नजरें केवल मानसून पर टिकी हैं। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी, जिससे फसलों को राहत मिलेगी और बाकी खेतों में भी समय रहते बोवनी पूरी हो सकेगी।

बीएससी स्टूडेंट को APK फाइल भेजी, 59 हजार ठगे

खंडवा में आरटीओ चालान के नाम पर ठगी, 50 हजार मांगने पर दो यूट्यूबर पर केस

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा में सेफ क्लिक अभियान चलाने के बाद भी साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक बीएससी छात्र को व्हाट्सएप पर आरटीओ चालान के नाम से एपीके फाइल भेजी गई और उससे 59 हजार रुपए की ठगी कर ली गई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली पुलिस के अनुसार, फरियादी करण पिता गुलसिंह डूडवे है, जो खरगोन जिले के भीकनगांव का रहने वाला है। फिलहाल वह खंडवा स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है। वह कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेश तलाई में किराए से रहता है।

पुलिस शिकायत में करण ने बताया कि 8 जुलाई को सुबह करीब 11:45 बजे उसके मोबाइल पर दो बार ट्रांजेक्शन के मैसेज आए। पहला ट्रांजेक्शन 49 हजार 999 रुपए का था। दूसरा ट्रांजेक्शन 8 हजार 999 रुपए का था। इसके बाद मैंने ट्रांजेक्शन के मैसेज देखे और अकाउंट का बैलेंस चेक किया तो मेरे अकाउंट से कुल 59 हजार 466 रुपए की धोखाधड़ी हो चुकी थी। यह सब आरटीओ चालान की एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद हुआ।

दो यूट्यूबर पर ब्लैकमेलिंग का केस: पंधाना थाना पुलिस ने दो यूट्यूबर के खिलाफ 50 हजार रुपए मांगने की शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने ब्लैकमेलिंग की धाराओं में यूट्यूबर गोपाल सावनेर और लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण केल्दे, दोनों निवासी पंधाना, को आरोपी बनाया है। शिकायत मोहनपुर पंचायत के सचिव रामप्रकाश मोरे ने की थी। उन्होंने बताया कि दोनों सड़क और नाली के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे। इसके बदले 50 हजार रुपए की मांग की गई।

इटारसी में 9वीं के छात्र के पसली में चाकू घोंपा, परीक्षा दे रहा छात्र गंभीर घायल

मीडिया ऑडीटर, इटारसी (निप्र)। इटारसी के नाला मोहल्ला क्षेत्र में मंगलवा रात पड़ोसी ने शराब के नशे में नौवीं कक्षा के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने नाबालिग की पसली में चाकू घोंप दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और 10-11 टांके आए हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार, नाला मोहल्ला निवासी धर्मेंद्र भदौरिया शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। रात करीब 10 बजे शंकर लाल चौरे का बेटा (15) अपनी परीक्षा की तैयारी के बीच किसी काम से घर से बाहर निकला था। इसी दौरान आरोपी धर्मेंद्र ने उसे रोका और बिना किसी पुरानी रंजिश के अचानक चाकू से हमला कर दिया। चाकू सीधे नाबालिग की पसली में लगा, जिससे वह लहूलुहान हो गया।

छात्र 9वीं में पढ़ता है: हमले का शिकार हुआ छात्र कक्षा 9वीं में पढ़ता है और इन दिनों उसकी परीक्षाएं चल रही हैं। घटना से छात्र और उसके परिवार को गहरा आघात लगा है। छात्र की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन परीक्षा के समय हुई इस घटना से परिजन चिंतित हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी धर्मेंद्र ने पुलिस से बचने के लिए खुद को भी ईंट मारकर घायल कर लिया। उसे भी तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लिया: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने बताया कि यह दो पड़ोसियों के बीच का विवाद था। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अवैध शराब परिवहन पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाइ 300 पाव देसी मसाला शराब व बाइक जब्त, आरोपी जेल भेजा

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। जिले में अवैध मदिरा के धारण, परिवहन, निर्माण एवं विक्रय पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग लगातार अभियान चला रहा है।

इसी क्रम में कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री विकास त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आबकारी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का परिवहन कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजीव थापक एवं श्रीमती साधना पटेल राजपूत के नेतृत्व में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी दल ने भेंरोखेड़ी तिराहा स्थित हैप्पी वाइव रेस्टोरेंट के पास ठठर रोड पर घेराबंदी की।

इस दौरान टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल क्रमांक MP40ZG3978 को रोककर उसकी तलाशी ली गई।

वाहन चालक की पहचान अंकित पिता मुकेश श्रीवास्तव (25 वर्ष), निवासी ग्राम क्षीरखेड़ा, थाना करारिया, जिला विदिशा के रूप में हुई। मोटरसाइकिल पर बंधे दो थैलों की तलाशी लेने पर उनमें से 300 पाव देसी मसाला मदिरा, कुल 54 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद की गई।

आबकारी विभाग ने आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। कार्रवाई के दौरान जब्त की गई अवैध मदिरा एवं दोपहिया वाहन का कुल अनुमानित बाजार मूल्य लगभग एक लाख रुपये आंका गया है।इस कार्रवाई को सफल बनाने में आबकारी उपनिरीक्षक संजय इवने तथा आबकारी आरक्षक पवन गौर, राहुल राठौर, प्रमोद धुर्वे, आशीष कौरव एवं प्रीति परिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

इंदौर हाईवे पर ऑटो पलटा, 4 महिलाएं घायल, बुरहानपुर में ट्रक के पास से गुजरने से हुआ अनियंत्रित

मीडिया ऑडीटर, बुरहानपुर (निप्र)। बुरहानपुर इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर बुधवार दोपहर करीब 12 बजे एक ऐपे ऑटो अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। हादसे में चार महिलाएं घायल हो गईं। सभी घायलों को डायल 112 और एंबुलेंस 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा शाहपुर फाटे से पहले होटल मन के पास हुआ। सभी महिलाएं मैथा खारी गांव की रहने वाली हैं। वे नसबंदी कैंप में शामिल होने के लिए बुरहानपुर जिला अस्पताल जा रही थीं।

पास से ट्रक के गुजरने से हुआ अनियंत्रित: घायल महिला ने बताया कि ऑटो के पास से एक ट्रक निकला। इसके बाद ऑटो अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया।डायल 112 की टीम ने तीन महिलाओं को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं एंबुलेंस 108 से प्रमिला नाथ को अस्पताल लाया गया। ऑटो में सवार कमला बाई ने बताया कि वाहन में छह से सात महिलाएं थीं।

मंदसौर में थमा मानसून, 8 दिन से अच्छी बारिश नहीं

तेज धूप-उमस से जनजीवन प्रभावित, किसान बारिश के इंतजार में, 17 जुलाई से मानसून की रफ्तार बढ़ने के आसार

मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मंदसौर जिले में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम सी गई है। पिछले करीब एक सप्ताह से जिले में अच्छी बारिश नहीं होने से गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। खेतों में नमी कम होने लगी है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने फिलहाल भारी बारिश की संभावना से इनकार किया है, हालांकि 17 जुलाई के बाद मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने के संकेत दिए हैं।

8 जुलाई के बाद नहीं हुई अच्छी बारिश:

जिले में आखिरी बार 8 जुलाई को अच्छी बारिश दर्ज की गई थी। इसके बाद 9 जुलाई की रात जिला मुख्यालय और कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन तब से अब तक कहीं भी उल्लेखनीय वर्षा नहीं हुई है। लगातार बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को बादलों के बावजूद राहत नहीं मिल रही।

तेज धूप और उमस ने बढ़ाई परेशानी:

बारिश का दौर थमने के बाद दिनभर तेज धूप और उमस का असर बना हुआ है। सुबह से शाम तक गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। आसमान में बादल तो छा रहे हैं, लेकिन बिना बरसे आगे बढ़ जाने से मौसम और अधिक उमस भरा हो गया है।

जिले के अधिकांश इलाके सूखे:

जिला मुख्यालय के अलावा भावगढ़, गरोठ, सुवासरा, शामगढ़, दलौदा, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, डिगांव, सुंठोद, बरखेड़ा और अफजलपुर सहित अधिकांश क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश नहीं हुई है। खेतों की मिट्टी की नमी तेजी से कम हो रही है, जिससे खरीफ फसलों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

किसानों की बढ़ी चिंता:

शुरुआती बारिश से किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई कर दी थी, लेकिन अब लगातार बारिश नहीं होने से फसलों की बढ़वार प्रभावित होने लगी है। किसान अच्छी वर्षा का इंतजार कर रहे हैं ताकि फसलों को पर्याप्त नमी मिल सके और उत्पादन प्रभावित न हो।

17 जुलाई के बाद सक्रिय हो सकता है मानसून:

मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल पश्चिमी मध्य प्रदेश में व्यापक बारिश की संभावना कम है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज-चमक की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन भारी वर्षा के आसार नहीं हैं। हालांकि, 17 जुलाई के आसपास मानसून के दोबारा सक्रिय होने और बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है।

अब तक 10.13 इंच बारिश दर्ज:

जिले में इस मानसून सीजन में अब तक औसतन करीब 10.13 इंच बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। शुरुआती वर्षा से खरीफ फसलों को फायदा मिला, लेकिन कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छी पैदावार के लिए आगामी दिनों में नियमित और संतुलित बारिश बेहद जरूरी होगी।

भारत का मेंस सिंगल्स अभियान समाप्त

● विमेंस सिंगल्स में उन्नति की हार

टोक्यो ,एजेंसी। 'जापान ओपन 2026' के मेंस सिंगल्स ड्रॉ में बुधवार को भारत की उम्मीदें खत्म हो गईं। 'बीडब्ल्यूएफ सुपर 750' टूर्नामेंट के शुरुआती दौर के मुकाबलों में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी दोनों बाहर हो गए, जबकि उन्नति हुड्डा भी विमेंस सिंगल्स प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। वर्ल्ड नंबर 14 खिलाड़ी लक्ष्य सेन टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में घरेलू खिलाड़ी कोकी वातानाबे का सामना नहीं कर सके। वातानाबे ने यह मुकाबला 21-16, 21-14 से अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ी शुरुआत से ही पिछड़ते नजर आए। वातानाबे ने दोनों सेट में मिड-गेम इंटरवल पर बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। वापसी की कोशिश के बावजूद, लक्ष्य मैच का रुख नहीं बदल सके और जापानी शटलर ने सिर्फ 38 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह वातानाबे की भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ सात मुकाबलों में तीसरी जीत रही। दूसरी तरफ, आयुष शेट्टी टूर्नामेंट में बने रहने के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन आखिरकार तीन गेम के कड़े मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी कुनलावुत वितिदसर्न से हार का सामना करना पड़ा। थाई स्टार ने कड़े मुकाबले वाले पहले गेम को 21-19 से अपने नाम किया, जिसमें उन्होंने सेट के ज्यादातर समय मामूली बढ़त बनाए रखी। आयुष ने दूसरे गेम में शानदार वापसी की। चार मैच प्वाइंट्स से उबरते हुए उन्होंने तनावपूर्ण मुकाबले में 25-23 से जीत हासिल करते हुए मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचाया। हालांकि, यह लय ज्यादा देर तक नहीं रही। कुनलावुत ने तीसरे गेम में फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और 21-15 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ कुनलावुत का आयुष के खिलाफ 'हेड-टू-हेड' रिकॉर्ड 2-1 हो गया। विमेंस सिंगल्स ड्रॉ में भी भारत को एक और झटका लगा। उन्नति हुड्डा को चीनी ताइपे की हुआंग यू-हसुन ने शिकस्त दी। पहला गेम 21-16 से गंवाने के बाद, उन्नति ने वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-16 से जीतकर मुकाबला बराबर किया, लेकिन हुआंग ने निर्णायक गेम 21-15 से अपने नाम करते हुए अगले दौर में जगह बना ली।इस प्रतियोगिता के सिंगल्स इवेंट में भारत की तरफ से सिर्फ पीवी सिंधु ही बची हैं। मिक्स्ड डबल्स जोड़ी तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला भी अभी मुकाबले में बने हुए हैं। मंगलवार को भारत की दोनों पुरुष डबल्स जोड़ियां बाहर हो गई थीं।

गिल की कप्तानी पारी, इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर भारत ने सीरीज में बनाई लीड

बर्मिंघम,एजेंसी। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया। टी20 सीरीज 0-4 से गंवाने के बाद मेहमान टीम ने इस दौरे पर आखिरकार जीत का खाता खोल लिया है। टीम इंडिया ने तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47.5 ओवरों में सिर्फ 258 रन पर ढेर हो गई। बेन डकेट और जैकब बेथेल की सलामी जोड़ी ने 12.2 ओवरों में 61 रन की साझेदारी की। बेथेल महज 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि डकेट ने 45 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 43 रन बनाए। सलामी जोड़ी के टूटने के बाद टीम लड़खड़ा गई। आलम ये रहा कि इंग्लैंड ने 21.4 ओवरों में 107 के स्कोर तक अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। यहां से लियाम डॉसन ने जो रूट के साथ सातवें विकेट के लिए 134 गेंदों में 121 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

डॉसन 83 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 68 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रूट ने 76 गेंदों में नाबाद 76 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 6 चौके शामिल रहे। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं। जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट चटकाया। इसके जवाब में भारत ने 45.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने अनुभवी रोहित शर्मा के साथ 7.3 ओवरों में 43 रन की साझेदारी की। रोहित 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगले ओवर में टीम ने विराट कोहली (5) का विकेट भी गंवा दिया। भारत ने 48 के स्कोर तक अपने 2 विकेट खो दिए थे। यहां से गिल ने श्रेयस अय्यर (35) के साथ तीसरे विकेट के लिए 103 गेंदों में 101 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया। 25.4 ओवर में क्रैंप के कारण कप्तान गिल मैदान से वापस लौट गए। उस समय तक गिल ने 75 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 80 रन बना लिए थे। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अक्षर पटेल के साथ छठे विकेट के लिए 105 गेंदों में 102 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। सुंदर ने 63 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 52 रन बनाए, जबकि पटेल 52 गेंदों में 57 रन बनाकर नाबाद रहे।

'उन्होंने मुझे मेरा गेम समझाया'

● सुंदर ने गंभीर और नेहरा को दिया अपनी बल्लेबाजी में हुए सुधार का श्रेय

बर्मिंघम ,एजेंसी। भारत के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों में 52 रनों की दमदार पारी खेली। सुंदर ने हेड कोच गौतम गंभीर और गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा को अपनी बैटिंग में बेहतर समझ विकसित करने का श्रेय दिया है। एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की छह विकेट से जीत में अहम नाबाद अर्धशतक लगाने के बाद उन्होंने कहा कि अलग-अलग फॉर्मेट में उनके विकास में इन दोनों के मार्गदर्शन ने बड़ी भूमिका निभाई है। सुंदर ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर 102 रनों की अटूट साझेदारी निभाई, जिसके दम पर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही। एक बल्लेबाज के तौर पर अपने विकास के बारे में बात करते हुए सुंदर ने कहा कि तैयारी और उनके आस-पास के लोगों द्वारा उन पर दिखाए गए भरोसे ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, 'मैं बहुत अच्छी तैयारी करने की कोशिश करता हूं। तैयारी के मामले में, मैं यह पक्का करता हूं कि मैं सब कुछ पूरी तरह से करूं। मैं तैयारी को बहुत महत्व देता हूं, और मैं बहुत आभारी हूं कि लोगों ने हमेशा मेरी काबिलियत पर भरोसा किया है। उन्होंने आगे कहा, 'यहां गौतम गंभीर ने हमेशा मुझे समझाया कि मैं बैट से असल में क्या कर सकता हूं, और मुझे अपना गेम समझने में भी मदद की।

गिल या बुमराह नहीं, पहले वनडे में इस खिलाड़ी को मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत ने एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। 259 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 28 गेंद बाकी रहते मुकाबला अपने नाम किया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो ऑलराउंडर अक्षर पटेल रहे, जिन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

गेंद और बल्ले दोनों से बने जीत के हीरो

अक्षर पटेल ने पहले गेंदबाजी में 9.5 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट लिए और इंग्लैंड को 258 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद जब भारत मुश्किल में था, तब उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ नाबाद 102 रन की साझेदारी करते हुए 52 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए और टीम को शानदार जीत दिला दी।

सीरीज के बाद इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती'

मैच के बाद अक्षर पटेल ने कहा, 'जिस तरह टी20 सीरीज गुजरी, उसके बाद इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। आज मैंने जैसा प्रदर्शन किया, उससे मैं बेहद खुश हूं।' उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर कहा, 'मेरा प्लान पेस में बदलाव करते हुए स्टंप-टू-स्टंप गेंदबाजी करने का था। मैंने उसी एरिया में गेंदबाजी की और चार विकेट मिले, इससे काफी खुशी है।'

मिल्खा सिंह का पहला गोल्ड, महिला हॉकी टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सबसे यादगार पल

नई दिल्ली ,एजेंसी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज 23 जुलाई से होने जा रहा है। इस इवेंट की मेजबानी स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर करेगा। भारत के 124 खिलाड़ी इस बार मेडल पाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। आइए आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सबसे यादगाल पलों के बारे में बताते हैं। मिल्खा सिंह का पहला गोल्ड मेडलः साल 1934 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला मेडल जीता था। यह मेडल कुश्ती में राशिद अनवर ने सिल्वर के रूप में दिलाया था। हालांकि, भारत को अपने पहले गोल्ड मेडल के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। देश को इस टूर्नामेंट में पहला गोल्ड कार्डिक में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 1958 में महान धावक मिल्खा सिंह ने दिलाया। मिल्खा ने 440 यार्ड स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया था।

मेजबानी में ऐतिहासिक प्रदर्शनः

भारत ने साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की और इस साल देश का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत की झोली में 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल आए। यानी भारत ने कुल मिलाकर 101 मेडल जीते। इस प्रदर्शन को भारत दोबारा कभी दोहरा नहीं सका है। हॉकी में ऐतिहासिक गोल्डः साल 2002 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने वो कर दिखाया था, जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करते हुए पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 17वें नंबर की रैंकिंग वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया था। फाइनल मुकाबले में भारत ने विश्व रैंकिंग में पांचवें नंबर की टीम इंग्लैंड को हराकर हर किसी को अपने खेल का मुरीद बना दिया था। भारतीय महिला हॉकी की इससे इन खेलों में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है।

● मनिका बत्रा का गोल्डः

साल 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका दिया था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल को अपने नाम किया था। वह टेबल टेनिस में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थीं। सात्विक-चिराग की जोड़ी का यादगार प्रदर्शनः साल 2022 में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इतिहास रचा था। पूरे टूर्नामेंट में अपने दमदार खेल के बूते वह गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे थे।

स्पेन दमदार खेल के साथ फाइनल में पहुंचा

सेमीफाइनल में फ्रांस को दी 2-0 से मात

नई दिल्ली,एजेंसी। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हराया। इस हार के बाद अब फ्रांस की टीम तीसरे स्थान पर रहने के लिए मुकाबला करेगी। फ्रांस का सामना दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली टीम से होगा। स्पेन ने विश्व कप के इतिहास में यह दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले, टीम ने साल 2010 में फाइनल का टिकट हासिल किया था और खिताब को अपने नाम करने में सफल रही थी। मैच की शुरुआत में फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और किलियन एम्बाप्पे ने स्पेन के डिफेंस पर दबाव बनाने का प्रयास किया। हालांकि, मुकाबले में पहली सफलता स्पेन के हाथ लगी। 19 वर्षीय खिलाड़ी लामिन यमाल को रोकने के प्रयास में फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्ने फाउल कर बैठे, जिसके चलते स्पेन को पेनल्टी मिल गई। मैच के 22वें मिनट में मिकेल ओयरजाबल ने बिना कोई गलती किए पेनल्टी को गोल में तब्दील करते हुए स्पेन को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद फ्रांस ने पहले हाफ में बराबरी करने की काफी कोशिश की, लेकिन टीम स्पेन के डिफेंस को नहीं भेद सकी। दूसरे हाफ में स्पेन का पूरी तरह से दबदबा देखने को मिला। मैच के 58वें मिनट में स्पेन के खिलाड़ी पेड्रो पोरो ने शानदार गोल करते हुए स्पेन की बढ़त को 2-0 कर दिया। 0-2 से पिछड़ने का दबाव साफतौर पर फ्रांस के खेल में नजर आया। टीम के कोच ने डेजिरे डुए और रयान चेर्की को मैदान पर उतारकर मैच की स्थिति को बदलने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एम्बाप्पे ने कई बार स्पेन के डिफेंस को भेदने की कोशिश की, लेकिन हर बार विपक्षी टीम के गोलकीपर उनाई सिमोन उनके आगे चट्टान की तरह खड़े नजर आए। फ्रांस की टीम निर्धारित 90 मिनट में कोई गोल नहीं कर सके और स्पेन ने मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। खिताबी मुकाबले में अब स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने तीन 'आईसीसी डेवलपमेंट अवॉर्ड' जीते

एडिनबर्ग,एजेंसी। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड आईसीसी डेवलपमेंट अवॉर्ड्स 2025 में सबसे बड़े विजेताओं में से एक बनकर उभरा। बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेल को बढ़ाने और महिला क्रिकेट के विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के लिए तीन वैश्विक सम्मान हासिल किए। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को ये अवॉर्ड एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। इस इवेंट में दुनिया भर के आईसीसी एसोसिएट सदस्यों के बेहतरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहल और प्रदर्शन का जश्न मनाया गया। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने अपनी खास 'गर्ल्स अंडर-15 एकेडमी लीग' के लिए 'मैरियट बॉनवॉय आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर' अवॉर्ड जीता। यह इस क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पहल थी। इसने युवा लड़कियों को प्रतियोगी क्रिकेट खेलने के ज्यादा मौके दिए और साथ ही सबको शामिल करने और अवसर देने को बढ़ावा दिया।

एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और तुर्की क्रिकेट को लगातार दूसरे साल, 'आईसीसी फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर' अवॉर्ड मिला। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को यह अवॉर्ड आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मिला। 'इंटरस्कूल क्रियो गल्फ कप' और 'गेट इनटू क्रिकेट - गर्ल्स ओनली' प्रोग्राम ने उन स्कूलों और समुदायों में इस खेल को पहुंचाया, जहां पहले लड़कियों के लिए मौके सीमित थे। यूएई ने 'आईसीसी एसोसिएट मेंबर विमेंस टीम परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर' अवॉर्ड भी जीता। महिला टीम का जिम्बाब्वे के खिलाफ अभियान यादगार रहा। वन-डे इंटरनेशनल का दर्जा मिलने के बाद अपनी पहली वनडे सीरीज में, यूएई ने चार मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई। इसके बाद उन्होंने टी20 सीरीज में जिम्बाब्वे को 2-0 से हराया, जो घर से बाहर किसी ऊंची रैंकिंग वाले 'पूर्ण सदस्य' देश के खिलाफ उनकी पहली सीरीज जीत थी। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सदस्य जायद अब्बास ने इन अवॉर्ड्स को यूएई क्रिकेट से जुड़े सभी लोगों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। उन्होंने कहा, 'ये अवॉर्ड एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट, अधिकारियों, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन हैं।

जापान में पंजाब एफसी, बेंगलुरु एफसी की शानदार जीत

एफसी गोवा को मिली हार

कुराते,एजेंसी। भारतीय फुटबॉल के लिए मंगलवार का दिन रोमांचक रहा। देश की टॉप डेवलपमेंटल टीमों का मुकाबला जापान की जे-लीग टीमों से हुआ। इस दौरान कहीं दबदबा देखने को मिला तो कहीं रोमांचक मुकाबले हुए। कुल मिलाकर दिन भारतीय टीमों के नाम रहा। पंजाब एफसी और बेंगलुरु एफसी ने दो मैच जीते, जबकि एफसी गोवा को करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दिन के सबसे शानदार प्रदर्शन में, पंजाब एफसी ने अविस्पा फुकुओका को 5-0 से करारी शिकस्त दी। पंजाब की टीम ने मैच की शुरुआत से ही जबरदस्त खेल दिखाया। सिंगमायुम शमी ने शुरुआती दौर में ही दो गोल (तीसरे और 28वें मिनट में) करके टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। ओमांग डोडम (42वें मिनट) और नगारिन शाइजा (55वें मिनट) ने बढ़त को और बढ़ाया, और आखिर में विशाल यादव ने स्टॉपेज टाइम (90+2 मिनट) में गोल करके जीत पर मुहर लगा दी। बेंगलुरु एफसी ने जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए गिरावांज किताक्युशु के खिलाफ 3-2 से मुश्किल जीत हासिल की। ??युंनोसुके इमाई के 40वें मिनट के गोल से पिछड़ने के बाद, बेंगलुरु ने दूसरे हाफ में वापसी की। रक्षित प्रिया अनिल ने 61वें मिनट में बराबरी का गोल किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण 'ओन गोल' की वजह से जापानी टीम मुकाबले में बनी रही, लेकिन सेर्टो वोर्नेइलेन कॉम के 75वें मिनट के गोल और आखिरी मिनटों में टीम के मजबूत डिफेंस (मोहम्मद अरबाश के 90वें मिनट के गोल के बावजूद) ने बेंगलुरु की जीत पक्की कर दी।

एफसी गोवा को एक कड़े मुकाबले में, सागन तोसु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। उन्हें जेनर्यू ओनो ने छठे मिनट में एकमात्र गोल करके हराया। दूसरे हाफ में ज्यादा समय तक गेंद पर कब्जा रखने और कई अच्छे मौके बनाने के बावजूद एफसी गोवा, जापानी टीम के अनुशासित डिफेंस को भेद नहीं पाई मैच 1-0 से हार गई।

राजिम की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राज्य शासन ने राजिमवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजिम नगर पंचायत की सीमाएं ही राजिम नगर पालिका की सीमाएं होंगी। राज्य शासन के इस निर्णय से पूरे शहर में खुशी एवं उत्साह का वातावरण है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राजिम नगर पंचायत के नगर पालिका के रूप में उन्नयन पर कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय से राजिम के सुनियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी तथा शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे राजिम में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, उद्यान, सामुदायिक भवन सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास को और ज्यादा गति मिलेगी। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी ढंग से नगरवासियों तक पहुंचेगा।

सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रायगढ़ जिला प्रशासन ने आज राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग के खिलाफ व्यापक संयुक्त अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गठित जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स ने शहर के प्रमुख यातायात क्षेत्रों में सघन प्रवर्तन अभियान चलाते हुए राजमार्गों से अतिक्रमण हटाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 से अधिक वाहनों पर लगभग 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह के निर्देशन में यह अभियान कांशीराम चौक, छातामुड़ा चौक तथा अन्य व्यस्त मार्गों पर संचालित किया गया। अभियान के दौरान एडीएम श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, एसडीएम श्री महेश शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा जिला परिवहन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने मैदानी स्तर पर कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाया। दुकानों के सामने किए गए सड़क विस्तार, अस्थायी शेड, अवैध निर्माण तथा अन्य बाधाओं को हटाते हुए संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान राजमार्गों और प्रमुख चौराहों के आसपास अवैध रूप से खड़े भारी वाहनों एवं अन्य गाड़ियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की गई। यातायात बाधित करने और दुर्घटना की आशंका बढ़ाने वाले 41 से अधिक वाहनों पर मौके पर ही चालानी कार्रवाई करते हुए लगभग 41 हजार रुपए का अर्थदंड वसूला गया। जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 15 मीटर की परिधि के भीतर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अथवा संबंधित मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, लाइसेंस अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इस अभियान की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जाएगी।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों को मिल रही सुरक्षा, आत्मविश्वास और अधिकारों की जानकारी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को लेकर व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र की टीम ने किया मूल्यांकन

किसानों से सीधे संवाद कर जानी मिट्टी परीक्षण कार्ड की उपयोगिता और प्रभाव

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) की विशेषज्ञ टीम ने बीते 9 एवं 10 जुलाई को दो दिवसीय रायगढ़ जिले का दौरा कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के क्रियान्वयन और उसके प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन किया। इस दौरान टीम ने जिले के ग्राम गोपालपुर, भगोरा, पाली, बायंग, नवरंगपुर एवं धनागर पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद स्थापित किया और मिट्टी परीक्षण कार्ड की वर्तमान स्थिति तथा उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी प्राप्त की। उप संचालक कृषि ने बताया कि दौरे के दौरान विशेषज्ञ दल ने किसानों से चर्चा कर यह जाना कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग वे अपनी खेती में किस प्रकार कर रहे हैं तथा इससे उत्पादन लागत एवं फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है। टीम ने किसानों को मृदा परीक्षण में शामिल प्रमुख पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश सहित अन्य सूक्ष्म एवं आवश्यक पोषक तत्वों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अध्ययन दल ने बताया कि मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग न केवल खेती की लागत को कम करता है बल्कि भूमि की उर्वरता को बनाए रखने और फसल उत्पादन बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर ही उर्वरकों और पोषक तत्वों का उपयोग करने की सलाह दी गई, जिससे वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा मिल सके। रायगढ़ जिले के किसानों की कृषि भूमि के मिट्टी परीक्षण की सुविधा के लिए पटेलपाली स्थित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित की जा रही है, जहां किसानों की भूमि के नमूनों का परीक्षण कर उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इस पहल से जिले के किसान वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निरीक्षण दल में अनुसंधान अधिकारी डॉ. राजेन्द्र सिंह बरेलिया, डॉ. प्रेम रतन पाण्डेय एवं श्री अखिलेश कुरील शामिल थे। वहीं इस अध्ययन एवं निरीक्षण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में कृषि विभाग के श्री अभिषेक पटेल एवं श्री संजय सिदार सहित अन्य अधिकारियों और मैदानी अमले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ग्राम स्तर पर भी कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। ग्राम गोपालपुर में श्रीमती रंजीता पैंकरा, ग्राम भगोरा में श्री सुशील चौरसिया, ग्राम पाली में श्रीमती जमीमा एक्का, ग्राम बायंग में श्री विकास साहू, ग्राम नवरंगपुर में श्री दयाशंकर नायक तथा ग्राम धनागर में श्रीमती योगेश्वरी पटेल ने किसानों और अध्ययन दल के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि की वास्तविक पोषण स्थिति की जानकारी मिल रही है, जिससे वे आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों का उपयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं।

सेवा सेतु बना नागरिकों के लिए भरोसेमंद माध्यम

चार दिन में जारी हुआ आय प्रमाण पत्र

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। शासन द्वारा नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु आमजन के लिए सुविधाजनक माध्यम बनता जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन एवं निर्धारित समय-सीमा में प्रमाण पत्र जारी होने से नागरिकों का समय और श्रम दोनों बच रहे हैं। इसी क्रम में रायगढ़ जिले के ग्राम कोसमपाली निवासी पंकज कुमार विश्वाल का आय प्रमाण पत्र सेवा सेतु के माध्यम से निर्धारित समयावधि में जारी किया गया। पंकज कुमार विश्वाल के पिता नवीन कुमार विश्वाल ने 5 जुलाई 2026 को लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया गया। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 9 जुलाई 2026 को तहसीलदार, रायगढ़ द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। नवीन कुमार विश्वाल ने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान रही। आवेदन जमा करने के बाद तय समय-सीमा के भीतर प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। इससे

उन्हें किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और बार-बार कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि आय प्रमाण पत्र समय पर मिलने से बच्चे के शैक्षणिक कार्यों सहित अन्य आवश्यक शासकीय प्रक्रियाओं में सुविधा मिलेगी। शासन द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की यह पहल आमजन के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। उल्लेखनीय है कि सेवा सेतु के माध्यम से आय, जाति, निवास सहित विभिन्न प्रमाण पत्रों एवं अन्य नागरिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल प्रणाली से सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है, प्रक्रियाएं सरल हुई हैं तथा नागरिकों को निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ सुनिश्चित हो रहा है।

महतारी वंदन योजना से मिली आर्थिक मजबूती

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के विकासखंड मोहला के ग्राम रामगढ़ निवासी श्रीमती केजू बाई सलामे इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अपनी मेहनत और लगन के साथ शासन की योजनाओं का लाभ लेकर उन्होंने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया है, बल्कि आज वे आत्मनिर्भरता की नई पहचान भी बन रही हैं।केवल आर्थिक सहयोग नहीं, व्यवसाय को आगे बढ़ाने बनी पूंजी' श्रीमती केजू बाई बिहान के रोशनी स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। समूह से जुड़ने के बाद उनमें

बचत एवं आर्थिक प्रबंधन की समझ बढ़ी और स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास मिला। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपने गांव में एक किराना दुकान का संचालन शुरू किया, जो आज उनके परिवार की आय का प्रमुख स्रोत बन चुकी है। वे बताती हैं कि महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए की सहायता राशि नियमित रूप से प्राप्त होती है।

साय सरकार के सुशासन में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मिली आर्थिक मजबूती

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप वनवासी एवं तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण की प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत पेण्ड्रारोड जिला लघु वनोपज सहकारी संघ के माध्यम से 9 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के 10 हजार 160 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1 करोड़ 39 लाख 36 हजार 718 रुपये की राशि एमएफपी कलेक्शन एंड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे अंतरित की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार वनवासी समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करने, उन्हें समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में जिले में 6593 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण के आधार पर बोनस राशि का वितरण किया गया। पूरी भुगतान प्रक्रिया डिजिटल एवं पारदर्शी माध्यम से संपन्न होने से हितग्राहियों को बिना किसी विलंब के सीधे उनके बैंक खातों में राशि प्राप्त हुई, जिससे संग्राहकों में प्रसन्नता का वातावरण है। वनमंडल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक श्रीमती ग्रीष्मी चांद के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान से हजारों वनवासी परिवारों को आर्थिक राहत मिली है। प्राप्त बोनस राशि का उपयोग हितग्राही कृषि कार्यों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक घरेलू जरूरतों की पूर्ति में कर सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए पारिश्रमिक का भुगतान 4 हजार रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पहले ही किया जा चुका था। अब प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि के भुगतान से तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। इससे न केवल वनवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी एवं हितग्राही-केंद्रित नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है।

सौर ऊर्जा से रोशन हुआ देवेंद्र का घर, बिजली बिल की चिंता से मिली हमेशा के लिए मुक्ति

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर भारी-भरकम बिजली बिल से हमेशा के लिए मुक्ति पाई जा सकती है। भारत सरकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी देती है। 1 किलोवाट के लिए 30 हजार रूपए, 2 किलोवाट के लिए 60 हजार रूपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए 78 हजार रूपए तक की वित्तीय सहायता सीधे आपके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। दंतेवाड़ा जिले के रहने वाले देवेंद्र झाड़ी के लिए अब हर महीने आने वाला बिजली का बिल कोई चिंता का विषय नहीं रहा। कुछ समय पहले तक वे भी महंगे बिजली बिलों से परेशान रहते थे, लेकिन आज उनके घर की छत पर लगे सोलर पैनल उनके परिवार के लिए बचत और खुशहाली की नई किरण लेकर आए हैं। यह सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए। दोहरी सब्सिडी का मिला लाभ देवेंद्र ने इस जन-कल्याणकारी योजना का लाभ

उठाकर अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित करवाया। इस प्लांट को लगाने के लिए उन्हें केंद्र और राज्य सरकार, दोनों की ओर से बेहतरीन सब्सिडी (वित्तीय सहायता) मिली।

सब्सिडी मिलने के कारण सोलर प्लांट लगाने का शुरुआती खर्च बहुत कम हो गया, जिससे देवेंद्र के लिए इसे लगवाना बेहद आसान हो गया। अपने अनुभव को साझा करते हुए देवेंद्र झाड़ी बेहद खुश नजर आते हैं। वे बताते हैं कि पहले हर महीने बिजली का बिल काफी अधिक आता था, जिससे घर का बजट प्रभावित होता था। लेकिन जब से सोलर पैनल लगा है, बिजली का खर्च न के बराबर हो गया है। अब हमारे घर के पंखे, लाइट और अन्य उपकरण सौर ऊर्जा से ही चलते हैं। इससे हमें बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिली है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर घर को आत्मनिर्भर बनाना और नागरिकों को महंगे बिजली बिलों से राहत दिलाना है। 3 किलोवाट तक के घरेलू सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है। यह स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जिससे प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। कोई भी इच्छुक नागरिक योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से सुरक्षित तरीके से प्लांट लगवा सकता है। देवेंद्र झाड़ी आज अपने पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। वे दूसरों को भी इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अगर आपके घर की छत पर खाली जगह उपलब्ध है, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। इससे न सिर्फ आपके पैसों की बचत होगी, बल्कि आप देश को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने में भी अपना योगदान देंगे। सरकार की इस योजना का फायदा उठाकर अपने घरों को सौर ऊर्जा से जरूर जोड़ें।

विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति नीति बनाने समिति गठित

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ सरकार ने अधोसंरचना विकास निगम (CIDC) के अंतर्गत आने वाले विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर, इन दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए एक नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस नीति के निर्धारण के लिए राज्य शासन द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है, जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

हरित क्रांति की ओर बड़ा कदम : एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत लाखों पौधों का होगा रोपण उद्योगों को 8,950 पीपल के पौधे लगाने की जिम्मेदारी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सक्रिय मानसून के बीच पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से राज्य शासन की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'एक पेड़ माँ के नाम' महाअभियान के तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। अभियान को प्रभावी और परिणाममुखी बनाने के लिए रायगढ़ जिले के कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में संचालित वृक्षारोपण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की तथा सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जनआंदोलन होनी चाहिए। उन्होंने अभियान में जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों, किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों, युवाओं, विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं तथा जागरूक नागरिकों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक रोपा गया पौधा आने वाले वर्षों में जिले की हरित पहचान बने। बैठक में वन मंडलाधिकारी ने बताया कि जिले के रायगढ़ वनमंडल एवं धरमजयगढ़ वनमंडल द्वारा वर्षा ऋतु 2026 के लिए वृहद कार्ययोजना तैयार कर अभियान को गति दी जा रही है। वन विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के वृक्षारोपण के साथ पौधों की सुरक्षा और जीवितता सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। रायगढ़ वनमंडल के अंतर्गत रायगढ़, खरसिया, घरघोड़ा एवं तमनार परिक्षेत्र के कुल 27 स्थलों में लगभग 448.49 हेक्टेयर क्षेत्र में

3 लाख 43 हजार 212 पौधों का रोपण किया जाएगा। यह कार्य राज्य कैम्पा मद के अंतर्गत संपादित होगा। वृक्षारोपण के लिए वन विभाग की हाईटेक रोपणियों में सागौन, जामुन, बेल, अर्जुन, आँवला, नीम सहित स्थानीय जलवायु के अनुरूप विभिन्न प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त पौधे तैयार किए गए हैं। अभियान के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, सेफ्टी जोन ब्लॉक वृक्षारोपण, ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौनी प्रजातियों का रोपण तथा वन्यप्राणी एवं पक्षी संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विशेष वृक्षारोपण भी किया जाएगा। प्रत्येक स्थल पर रोपण प्रभारी एवं सहायक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो पौधों की सुरक्षा, देखभाल एवं नियमित निगरानी सुनिश्चित करेंगे। वन विभाग द्वारा संचालित किसान वृक्ष मित्र योजना के माध्यम से निजी भूमि पर भी वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष वनमंडल के 44 कृषकों द्वारा लगभग 83.11 एकड़ भूमि पर साधारण सागौन, बांस एवं क्लोनल नीलगिरी के 50 हजार 118 पौधे लगाए जाएंगे। इससे किसानों को भविष्य में अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा तथा पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। इसी कड़ी में कलेक्टर ने जिले में स्थापित सभी बड़े उद्योगों एवं कंपनियों को भी पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम से जोड़ते हुए उनके परिसरों एवं आसपास के क्षेत्रों में पीपल के पौधों का वृहद स्तर पर रोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी जिला पर्यावरण विभाग को सौंपी गई है। विभाग द्वारा पौधों के वितरण से लेकर उनके रोपण एवं संरक्षण तक की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।

उद्यानिकी विभाग द्वारा जिले की विभिन्न शासकीय उद्यान रोपणियों में पीपल के पौधे तैयार कर उद्योगों एवं कंपनियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शासकीय उद्यान रोपणी बोईरदादर से 3,200, घरघोड़ा स्थित संजय निकुंज उद्यान रोपणी से 1,250, कंजारा (लैलूंगा) रोपणी से 3,700 तथा धरमजयगढ़ रोपणी से 800 पौधों का वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार जिले में कुल 8 हजार 950 पीपल के पौधे उद्योगों एवं कंपनियों द्वारा लगाए जाएंगे। इस अभियान में जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ एवं सार्वजनिक उपक्रम सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएंगे। इनमें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, अडानी पावर, एमएसपी स्टील एंड पावर, नलवा स्टील एंड पावर, शाकंभरी स्टील्स, एनआर इस्पात एंड पावर, सिंघल एनर्जी, सालासार स्टील एंड पावर, अंजनी स्टील्स, रायगढ़ इस्पात एंड पावर, स्केनिया स्टील एंड पावर्स, अंबुजा सीमेंट्स, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स, हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, एसईसीएल सहित जिले की अनेक औद्योगिक एवं खनन इकाइयाँ शामिल हैं, जिन्हें संबंधित उद्यान रोपणियों से पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि पौधारोपण केवल लक्ष्य पूर्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि लगाए गए प्रत्येक पौधे के संरक्षण, नियमित देखभाल और जीवित रहने की दर की भी लगातार समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों और संबंधित उद्योगों को निर्देशित किया कि अभियान को जनसहभागिता से जोड़ते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण का स्थायी जनआंदोलन बनाया जाए। वनमंडलाधिकारी ने जिले के नागरिकों, किसानों, जनप्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें, अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उन्हें संरक्षित कर हरित, स्वच्छ एवं पर्यावरण-संतुलित रायगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी
आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा